नई दिल्ली
गुरुवार
26 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 83
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



कैबिनेट : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में...पेज-05

DELHIN/2014/58158

भाजपा का 'प्लान 55', यूपी में जिन सीटों पर अब...पेज-08

एक नजर

भारत पर 25 फीसदी टैरिफ का अमेरिकी प्रस्ताव, व्यापार समझौते से घट सकती है दर

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत के बीच वाशिंगटन ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, दोनों देशों के बीच औपचारिक व्यापार समझौता होने की स्थिति में यह दर घटाकर 17 प्रतिशत की जा सकती है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्ताव रखा। यूएसटीआर के मुताबिक, भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। यह शुल्क पहले से लागू सेक्शन 301 टैरिफ के अतिरिक्त होगा। हालांकि, कुछ उत्पादों को प्रस्तावित शुल्क से छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। कार्यालय ने कहा कि यदि भारत अमेरिका के साथ पारस्परिक व्यापार समझौता करता है तो अतिरिक्त टैरिफ की दर 17 प्रतिशत तक रखी जा सकती है। प्रस्तावित दर के अनुसार, भारत पर लगने वाला 17 प्रतिशत शुल्क बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड पर प्रस्तावित 18 प्रतिशत टैरिफ से कम होगा। वहीं, वियतनाम पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया जाना है। चीन पर भी मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 20 प्रतिशत टैरिफ निर्धारित किया गया है। यूएसटीआर ने अपनी जांच में भारत की विनिर्माण नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता को अमेरिकी व्यापार के लिए अनुचित और बाधा उत्पन्न करने वाला बताया है। कार्यालय का कहना है कि भारत की ये नीतियां 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत कार्रवाई योग्य हैं। इसी आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

सीतारमण ने स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विशेषज्ञों के साथ की 12वीं बजट पूर्व बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और खेल क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ बुधवार को केंद्रीय बजट 2027-28 को लेकर चर्चा की। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 12वीं पूर्व-बजट परामर्श बैठक में स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और खेल क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ चर्चा की गई। अगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए आयोजित बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिवों; खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी भाग लिया, ताकि बजट बनाते समय देश की प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण किया जा सके। वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट से पहले उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों, राज्य सरकारों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बजट पूर्व परामर्श बैठकें करता है, ताकि बजट में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के सुझावों को शामिल किया जा सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल : निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना लाई सरकार



नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (सीआईई) विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र योजना को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य सीआईई और इसके पुर्जों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। योजना की अवधि 8 वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक) होगी। योजना के दो घटक हैं, पहला बिक्री-आधारित प्रोत्साहन और सीआईई परीक्षण सुविधा। ब्रिक्री आधारित प्रोत्साहन के तहत पात्र ओईएम और पुर्जा निर्माताओं के लिए पांच वर्षों में होने वाली अतिरिक्त बिक्री पर 13 से 8 प्रतिशत तक का श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं परीक्षण सुविधा के तहत एक समर्पित परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए 375 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सीआईई इकोसिस्टम के निर्माण से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। सप्लाई चेन की सुरक्षा बेहतर होगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी।

विमानन एमआरओ के लिए सिंगापुर गणराज्य के साथ एमओयू को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल सुविधा के लिए सिंगापुर के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल क्षेत्र में कौशल और उद्योग विकास में सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर गणराज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के इस फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। वैष्णव ने बताया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विमानन एमआरओ हब बनाना और भारतीय एयरलाइंस की विदेशी रखरखाव केंद्रों पर निर्भरता को कम करना है। इस समझौता ज्ञापन से रखरखाव संबंधी कौशल विकास सुदृढ़ होगा और मरम्मत एवं ओवरहॉल सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।

एमओयू के प्रमुख प्रावधान-

विमान रखरखाव अभियंता प्रशिक्षण के लिए उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का संयुक्त रूप से विकास करना।

गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संस्थानों की विशेषज्ञता बढ़ाना तथा उनकी क्षमता का विकास करना।

भारतीय छात्रों को व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव प्रदान करने के लिए सिंगापुर की एमआरओ कंपनियों के साथ इंटर्नशिप और आदान-प्रदान कार्यक्रमों की व्यवस्था।

एमआरओ सुविधाओं के विस्तार में सहयोग के लिए भारतीय और सिंगापुर के उद्योग जगत के हितधारकों के बीच साझेदारी सुगम बनाना।

शिवसेना विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश



नई दिल्ली। शिवसेना के नाम, चुनाव चिह्न और विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में बुधवार को उच्चतम न्यायालय में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दलीलें पेश की गईं। ठाकरे गुट ने उच्चतम न्यायालय को आगाह किया कि यदि 'असहमति' की आड़ में राजनीतिक निष्ठा बदलने की अनुमति दी गई तो महज कुछ विधायकों को तोड़कर देश में किसी भी चुनी हुई सरकार को अस्थिर किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाबी दलीलें रखीं। सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने एक गंभीर संवैधानिक गलती की है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के पास मौजूद विधायी बहुमत को ही इस बात का आधार मान लिया कि वही 'असली शिवसेना' है। सिब्बल ने संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि केवल विधायकों के बहुमत के आधार पर किसी 'विधायी दल' को 'असली राजनीतिक दल' नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि चुने हुए विधायक मूल राजनीतिक दल के अधीन होते हैं, न कि वे स्वयं राजनीतिक दल बन जाते हैं। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने ठाकरे गुट से दसवीं अनुसूची के तहत 'असहमति' और 'दल-बदल' के बीच का अंतर स्पष्ट करने को कहा था। इस पर सिब्बल ने दलील दी कि अपने ही दल के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जाकर विपक्षी दल (भाजपा) के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का दावा करना 'असहमति' नहीं बल्कि स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने (दल-बदल) का स्पष्ट मामला है। सिब्बल ने न्यायालय के ध्यान में लाया कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार राजन सालवी के खिलाफ जाकर शिंदे गुट के 37 विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को वोट दिया था, जो पार्टी व्हीप का सीधा उल्लंघन था। शिंदे गुट की इस दलील पर कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में चुनाव-पूर्व गठबंधन तोड़कर महाविकास आघाड़ी (एमवीए) बनाया था, सिब्बल ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के सुबह के शपथ ग्रहण का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या उस समय उन दोनों दलों के बीच चुनाव-पूर्व गठबंधन था? सिब्बल ने कहा कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार खत्म नहीं हो जाता क्योंकि अयोग्यता याचिकाएं और स्पीकर का फैसला कार्यकाल के दौरान ही आया था।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात शुरू होने से पहले एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था अनिवार्य करेगा एनएचएआई

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात शुरू करने से पहले घटना प्रबंधन सेवाओं (आईएमएस) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राजमार्गों पर एम्बुलेंस, गश्ती वाहन और खराब वाहनों को हटाने के लिए टो-अवे क्रेन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य सड़क हादसों, वाहन खराब होने और अन्य आपात स्थितियों में राजमार्ग यात्रियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इन सेवाओं को एनएचएआई की राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 से जोड़ा जाएगा। साथ ही मौके पर तैनात टीमों का स्थानीय पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और अस्पतालों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले से संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के आंकड़ों और संबंधित मार्ग की जरूरत के आधार पर टोल प्लाजा या अन्य उपयुक्त स्थानों पर एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। मंत्रालय की ओर से एनएचएआई को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंस की तैनाती केंद्रीयकृत एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्धारित अधिकार दिए गए हैं। वहीं गश्ती वाहनों और टो-अवे क्रेन की व्यवस्था अलग-अलग निविदाओं या राजमार्गों के रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के तहत की जाएगी। इसके अलावा ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो मंत्रालय की ओर से एनएचएआई को नहीं सौंपे गए हैं, लेकिन जिन पर एनएचएआई टोल वसूलता है, वहां भी घटना प्रबंधन सेवाओं की तैनाती मंत्रालय की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी। ऐसे मार्गों पर एम्बुलेंस एनएचएआई की केंद्रीयकृत एजेंसी के माध्यम से मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या एनएचएआईडीसीएल के समन्वय से तैनात की जाएंगी। गश्ती वाहनों और टो-अवे क्रेन की व्यवस्था संबंधित प्राधिकरण करेगा।

शेख हसीना का प्रत्यर्पण उनके और बंगलादेश सरकार के बीच का मामलाः भारत



नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने बंगलादेश की निर्वासित नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह पूर्व प्रधानमंत्री और बंगलादेश सरकार के बीच का मामला है। भारत ने बंगलादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को यहां नियमित मीडिया ब्रीफिंग में सुश्री हसीना के प्रत्यर्पण और देश लौटने की उनकी घोषणा के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री और वहां की सरकार के बीच का है और इस बारे में उनके पास इसके अलावा कुछ और कहने को नहीं है।

सुश्री हसीना के प्रत्यर्पण के बारे में उन्होंने कहा कि बंगलादेश की ओर से जो प्रत्यर्पण का अनुरोध आया है उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक किसी नागरिक के अपने देश लौटने का सवाल है और उसके लिए किस प्रकार के यात्रा दस्तावेज जरूरी हैं वह प्रत्यर्पण के अनुरोध से एक अलग मामला है। प्रवक्ता ने बंगलादेश में हिंसा की घटनाओं के बारे में कहा, 'जो हिंसा की वारदातें हुई हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हम उस पर चिंता व्यक्त करते हैं और बंगलादेश सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन मुद्दों की जांच होगी और जो लोग इनके पीछे हैं उन को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।' दोनों देशों के बीच गंगा जल बंटवारा संधि के बारे में पूछे जाने उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों के लिए एक स्थापित तंत्र है। दोनों देशों के बीच इस बात के लिए एक संयुक्त नदी आयोग है जो गंगा सहित सभी नदी मुद्दों पर नजर रखता है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच 1996 में हुई इस संधि की अवधि आगामी 12 दिसम्बर को समाप्त हो रही है।

एक लाख युवा बनेंगे 'नल जल मित्र', गांवों में संभालेंगे जलापूर्ति की जिम्मेदारी

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इन युवाओं को 'नल जल मित्र' के रूप में तैयार किया जाएगा, जो गांवों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने बुधवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य मंत्री वी.



सोमन्ना और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक केके मीणा ने कहा कि देश में करीब 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। अब इन जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। कार्यक्रम के तहत कम से कम एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन दिया जाएगा। इसपर करीब 111.93 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसकी पूरी राशि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वहन करेगा।

सपा की सूची पर इमरान मसूद बोले- हम भिखारी नहीं हैं

नई दिल्ली,एजेंसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी और दिल्ली में बैठकें हो रही थीं। ऐसे में बातचीत के बीच लखनऊ से उम्मीदवारों की घोषणा करना गठबंधन की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सपा से 26 सीटें मांगी ही नहीं थीं और उनकी पार्टी भिखारी नहीं है। इमरान मसूद ने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा कि एक तरफ गठबंधन की बातचीत की जा रही है और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। यह तरीका गठबंधन के लिए उचित नहीं है। इस घटनाक्रम से उन्हें ठेस पहुंची है। उनकी पार्टी अब इस पर आंतरिक चर्चा करेगी कि आगे बातचीत जारी रखनी है या नहीं। इस संबंध में अंतिम फैसला पार्टी ही करेगी।

☐26 सीटें मांगी ही नहीं थीं



मसूद ने कहा कि सपा ने 26 सीटों का प्रस्ताव देने और उन सीटों पर कांग्रेस के कम वोट मिलने का तर्क दिया है। क्या कांग्रेस को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि सपा को किन सीटों पर कितने वोट मिले थे। मसूद ने कहा कि कांग्रेस ने न तो 26 सीटें मांगी थीं और न ही किसी खास सीट को देने का आग्रह किया था। इसके बावजूद उन सीटों की घोषणा कर दी गई, जिनकी मांग कांग्रेस ने की ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन को गंभीरता और आपसी भरोसे के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराना है और पार्टी अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस दिशा में प्रतिबद्ध है। मसूद ने कहा कि सपा को तय करना चाहिए कि वह भाजपा से मुकाबला करना चाहती है या कांग्रेस से। यदि यही तरीका है तो सपा सभी 400 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। मसूद ने कहा कि उन्हें किसी की राय से आपत्ति नहीं है। वह अपनी पार्टी को मजबूत करने और अपने नेता के रुख के साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सपा ने जिन पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, उसमें सहारनपुर जिले की बेहट सीट से उमर अली खान और सहारनपुर सीट से आशु मलिक को फिर उम्मीदवार बनाया गया है। शामली जिले की कैराना सीट से नाहिद हसन और अमरोहा सीट से महबूब अली को भी दोबारा मौका दिया गया है। वहीं, ललितपुर सीट से ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची में चार मौजूदा विधायक हैं, जबकि ज्योति लोधी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। सपा की इस घोषणा को कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के बीच महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। बेहट और सहारनपुर दोनों सीटें कांग्रेस की संभावित मांग वाली सूची में शामिल बताई गई हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की भी इन सीटों पर दावेदारी और उम्मीदवार चयन में अपनी पार्टी की भूमिका को लेकर रुचि रही है। ऐसे में सपा की ओर से दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से आपत्ति सामने आई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही है। 24 नवंबर को दोनों दलों के नेताओं के बीच दूसरे दौर की बैठक करीब साढ़े तीन घंटे चली थी।

दिल्ली में अगले साल शुरू होंगे दो अस्पताल, 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का भी लक्ष्य

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अगले साल सिरसपुर और हस्तसाल में दो बड़े अस्पताल शुरू हो जाएंगे। इन दोनों अस्पतालों में कुल 1,815 बेड होंगे, जिससे राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलेगी। साथ ही 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगले महीने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 102वें जन्मदिवस के अवसर खोलने का लक्ष्य है।



मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार केवल नए अस्पताल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि मरीजों को अस्पतालों में बेहतर उपचार, आधुनिक चिकित्सा उपकरण, पर्याप्त डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हों। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत कर रही है ताकि लोगों को सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो और जनहित से जुड़े कार्यों में पूरी जिम्मेदारी, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसपुर में 1,164 बेड का अस्पताल तैयार हो चुका है। अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया चल रही है, जिसे जनवरी के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। हस्तसाल में 651 बेड के अस्पताल का निर्माण भी लगभग पूरा होने को है। इसे भी अगले वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। दोनों अस्पतालों के शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और मौजूदा अस्पतालों पर रोगियों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 415 केंद्र संचालित हो रहे हैं। सरकार ने अगले माह और 40 केंद्रों को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, अधिक रोगी आने वाले आरोग्य मंदिरों में दो पारियों में सेवाएं शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर समय पर उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मादीपुर और ज्वालापुरी में भी 691-691 बेड के अस्पताल विकसित कर रही है। दोनों परियोजनाओं की निर्माण अवधि वर्ष 2028 तक निर्धारित है। मादीपुर अस्पताल 466.50 करोड़ रुपये और ज्वालापुरी अस्पताल 484.04 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा अस्पतालों में भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 463 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक विकसित किया जा रहा है। ओपीडी ब्लॉक उद्घाटन के लिए तैयार है। राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल में 270 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर में 460 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक लगभग पूरा हो चुका है। इन्हें जल्द शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। लोकनायक अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर के एकीकृत पुनर्विकास की योजना पर भी काम चल रहा है। परियोजना के तहत योजना और निर्माण सहित लगभग 30 माह की अवधि निर्धारित की गई है। यमुनापार के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) को एक साझा संस्थागत ढांचे के अंतर्गत लाने का कार्य जारी है।

दिल्ली दंगा: शरजील और उमर खालिद की नई जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित शरजील इमाम और उमर खालिद की ओर से दाखिल नयी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को इन दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बंधी है और न्यायिक अनुशासन का पालन करना जरूरी है। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा था कि वो उच्चतम न्यायालय के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई योग्य नहीं हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय गए थे लेकिन 5 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हालांकि, 5 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी थी। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 22 मई को आरोपित खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी। इस मामले के चार आरोपितों सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में 18 आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।

सौरव दास विदेश जाने से रोके जाने पर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, आज सुनवाई

नई दिल्ली। काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने विदेश जाने से रोकने के सरकारी अधिकारियों के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सौरव दास की ओर से पेश वकील ने मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले की आज ही तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन न्यायालय ने मामले की सुनवाई कल यानि 26 नवंबर को करने का आदेश दिया।

सौरव दास के वकील ने कहा कि उनकी फ्लाइट 26 नवंबर की शाम को है और कोर्ट ने 26 नवंबर को ही सुनवाई करने का आदेश दिया। इससे पहले सौरव दास को 23 नवंबर की रात को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया। दास को कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जाना था। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनियन की ओर से आयोजित एक पैनल चर्चा भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भी कॉकरोच मूवमेंट के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इमिग्रेशन विभाग के अनुसार उनके पासपोर्ट के विवरण में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थीं। पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर को उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे इस गड़बड़ी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया और पूछा गया कि उनका पासपोर्ट जब्त क्यों न किया जाए।

आंगनवाड़ी बहनों के योगदान को मंत्री कपिल मिश्रा ने किया सम्मानित

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कार्यालय उत्तर-पूर्व द्वारा 9वें पोषण माह के अंतर्गत 'हमारी आंगनवाड़ी-हमारी जिम्मेदारी' अभियान के तहत 'आंगन का मिलन' कार्यक्रम का आयोजन करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैंप कार्यालय सोनिया विहार में किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के विकास, कला, संस्कृति एवं भाषा और पर्यटन मंत्री एवं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कपिल मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।



कार्यक्रम का मुख्य संदेश 'सशक्त बालक- सशक्त भारत' रहा। इस अवसर पर आंगनवाड़ी बहनों के सेवा, समर्पण एवं समाज निर्माण में योगदान को सम्मानित किया गया और उन्हें आंगनवाड़ी किट वितरित की गईं। मंत्री कपिल मिश्रा ने आंगनवाड़ी बहनों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य और समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्र केवल पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के भविष्य को मजबूत बनाने की आधारशिला हैं। उनकी मेहनत, संवेदनशीलता और सेवा भावना समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान वास्तव में समाज की उस शक्ति का सम्मान है, जो निस्वार्थ भाव से देश की भावी पीढ़ी के निर्माण में जुटी हुई है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में तुकमीरपुर और सोनिया विहार सहित विभिन्न क्षेत्रों में विधायक कार्यालयों के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। महिलाएं अपनी समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं को लेकर सीधे उनसे संपर्क कर सकती हैं। जनसेवा और लोगों के बीच उपलब्ध रहना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हित में सरकार द्वारा कार्य, रोजगार, वेतन और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी है और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी बहनों के साथ संवाद, सम्मान एवं सहभागिता का वातावरण रहा। मंत्री ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओं के साथ जुड़ाव और सामूहिक सहभागिता को मजबूत करने की बात कही।

दिल्ली में जुटेंगे देशभर के हुनरमंद कारीगर, 27 नवंबर से सजेगा हस्तशिल्प और कला का बाजार



नई दिल्ली। 'कारीगर बाजार' के दूसरे संस्करण का आयोजन 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक यहां के लोधी रोड स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। दस दिन के इस आयोजन में 26 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 250 से अधिक कारीगर और शिल्पकार अपनी कला एवं हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार और संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकारों के साथ जीआई टैग प्राप्त कला के विशेषज्ञ, पारंपरिक बुनकर, महिला कारीगर, स्वयं सहायता समूह और उभरते हुए उद्यमी शामिल होंगे। बाजार में बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी और इकत जैसे पारंपरिक वस्त्रों के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग, चिकनकारी, कच्छ कढ़ाई, मधुबनी, गोंड चित्रकला, टेराकोटा, ब्लू पॉटरी, धातु एवं लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक आभूषण और पर्यावरण अनुकूल हस्तशिल्प उत्पादों की विविधता देखने को मिलेगी। इस बार 'कारीगर एक्सपीरियंस सेंटर' भी विशेष आकर्षण होगा, जहां आगंतुक बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, चित्रकला और नक्काशी जैसी पारंपरिक कलाओं का लाइव प्रदर्शन देख सकेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को उत्पादों के साथ-साथ उनके पीछे की कला, तकनीक और कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत से जोड़ना है। कारीगर बाजार के निदेशक एवं सह-संस्थापक आमिर खान ने कहा कि पिछले संस्करण को मिले उत्साहजनक प्रतिसाद के बाद इस बार आयोजन को और व्यापक स्वरूप दिया गया है। मंच का उद्देश्य कारीगरों को पहचान और बाजार उपलब्ध कराना तथा उन्हें सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना है। निदेशक एवं सह-संस्थापक पंकज सिंह राणा ने कहा कि कारीगर बाजार के माध्यम से देश की विविध शिल्प परंपराओं को व्यापक पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं से लेकर छोटे कारीगर समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों तक, सभी को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

माटी कला के लाइव डेमो से लेकर आकर्षक छूट तक, दर्शकों को लुभा रहा झारखंड पवेलियन

नई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में झारखंड पवेलियन में माटी कला बोर्ड द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने की लाइव डेमो प्रस्तुति लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चाक पर मिट्टी को आकार देकर पारंपरिक तकनीक से सुंदर कलाकृतियां तैयार करते कारीगरों को देख दर्शक इस कला को करीब से समझने और जानने में रुचि दिखा रहे हैं। इस अवसर पर हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विभाग की निदेशक प्रीति रानी ने मिट्टी के बर्तन बनाने की लाइव डेमो प्रस्तुति में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वयं चाक पर मिट्टी को आकार देकर झारखंड की पारंपरिक माटी कला का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की मिट्टी में यहां की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय कारीगरों की रचनात्मकता की अनूठी पहचान समाहित है। माटी कला केवल एक शिल्प नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह के लाइव डेमो से लोगों को स्थानीय कलाकारों की मेहनत और हुनर को करीब से जानने का अवसर मिलता है। मेले के समापन के करीब पहुंचने के साथ ही झारखंड पवेलियन के विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट भी दी जा रही है। कई स्टॉलों पर चयनित उत्पादों की खरीद पर 20 से 30 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है। इससे आगंतुक झारखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक वस्तुओं की खरीदारी आकर्षक कीमतों पर कर सकते हैं। झारखंड पवेलियन में कला, संस्कृति, पारंपरिक हुनर और किफायती खरीदारी का यह संगम मेले के अंतिम दिनों में भी आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है।

निगमायुक्त संजीव खिरवार ने रोहिणी क्षेत्र का किया निरीक्षण, भलस्वा लैंडफिल साइट पर बायो माइनिंग कार्यों का लिया जायजा

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने बुधवार को बाहरी उत्तर क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर-23 का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निगमायुक्त ने इलाके में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। संजीव खिरवार ने बाहरी उत्तर क्षेत्र के वार्ड नंबर-27, बेगमपुर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने इलाके में सफाई व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त बनाए रखने के आदेश दिए। रोहिणी सेक्टर-32 एवं दीप विहार का भी निरीक्षण किया एवं वहां पर धूल कम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम दिल्ली को साफ, स्वच्छ एवं हरित शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कार्य करते हुए निगम के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं।



निरीक्षण के दौरान बाहरी उत्तर क्षेत्र के उपायुक्त राघवेंद्र मीणा सहित दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही, संजीव खिरवार ने आज भलस्वा लैंडफिल साइट पर जारी बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। निगमायुक्त ने भलस्वा लैंडफिल साइट कचरे के निस्तारण की प्रगति का जायजा लिया और कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर बचे कूड़े को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। निगमायुक्त ने भलस्वा लैंडफिल साइट पर जमा नए कूड़े के निस्तारण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर जमा लीगेसी कचरे के निस्तारण के मासिक लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाने चाहिए ताकि लीगेसी कचरे का समय से निस्तारण हो सके। उन्होंने भलस्वा लैंडफिल साइट पर आ रहे नए कूड़े का निस्तारण भी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख अभियंता के के शर्मा सहित दिल्ली नगर निगम के उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सिरसा ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पंजाब सरकार के दावे पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार की ओर से जारी आंकड़ों पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाए हैं। सिरसा ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने 632 दिनों में नशे से जुड़े मामलों में 94,746 लोगों की गिरफ्तारी का आंकड़ा पेश किया है, लेकिन यह आंकड़ा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के बयान का जिक्र करते हुए सरकार के दावे को चुनौती दी। भाजपा मुख्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिरसा ने आरोप लगाया कि आआपा सरकार नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय छोटे अपराधों में मामले दर्ज कर रही है, ताकि आरोपियों को बाद में जमानत मिल सके। यदि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वास्तव में नशा तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया होता, तो उन्हें इतनी आसानी से जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिलता। सिरसा ने पंजाब की जेलों की कुल क्षमता का हवाला देते हुए सरकार के गिरफ्तारी संबंधी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब की जेलों में लगभग 26 हजार कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि सरकार 632 दिनों में करीब 94 से 95 हजार लोगों को नशे से जुड़े अपराधों में गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि यदि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नशा तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, तो वे सभी जेलों में क्यों नहीं हैं? उन्होंने दावा किया कि वास्तविक नशा तस्करी के मामलों में आरोपियों के लिए जमानत हासिल करना आसान नहीं होता। उनके अनुसार, सरकार के आंकड़े और जेलों की क्षमता के बीच का अंतर उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। दिल्ली के मंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ छोटी धाराओं में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे आरोपियों को बाद में जमानत मिल जाती है। सरकार गिरफ्तारी के बड़े आंकड़े पेश करके नशे के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है, जबकि वास्तविकता में गंभीर नशा तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

ई-रिक्शा में पत्नी-बच्चों को बैठाकर करते थे लूटपाट, दो महिलाओं समेत परिवार के चार सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। ई-रिक्शा में पत्नी और बच्चों को साथ बैठाकर यात्रियों से लूटपाट करने वाले एक परिवार का पूर्वी जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि परिवार के सदस्य ई-रिक्शा में सवारी बनकर बैठते थे और महिलाओं व बच्चों की मौजूदगी में यात्रियों को शक नहीं होने देते थे। इसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू की नोक पर लूटपाट करते थे। आरोपियों ने 14 नवंबर की रात धर्मशिला पुल के पास एक यात्री से पांच हजार रुपये, आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र लूट लिया था।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित राजेश कुमार ने 14 नवंबर की रात करीब 10:59 बजे पीसीआर कॉल कर लूट की सूचना दी थी। उसने बताया कि ई-रिक्शा चालक ने दो महिलाओं और दो बच्चों की मौजूदगी में चाकू दिखाकर उससे पांच हजार रुपये लूट लिए। जांच में पता चला कि राजेश रात करीब 10:30 बजे नोएडा टी-पॉइंट से आनंद विहार बस टर्मिनल जाने के लिए डीएल7ईआर नंबर के ई-रिक्शा में सवार हुआ था। ई-रिक्शा में पहले से दो महिलाएं और दो बच्चे बैठे हुए थे। रास्ते में चालक ने ई-रिक्शा धर्मशिला अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। उसने राजेश को बताया कि उसे पत्नी और बच्चों को घर छोड़ना है। इसके बाद वह उसे धर्मशिला पुल के पास सुनसान जगह पर ले गया। वहां चाकू दिखाकर पांच हजार रुपये, आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र छीन लिए। आरोप है कि ई-रिक्शा में मौजूद दोनों महिलाओं ने भी पीड़ित को डराया और चालक की मांग मानने के लिए दबाव बनाया। इस मामले में न्यू अशोक नगर थाने में एफआईआर नंबर 823/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4)/3(5) में मामला दर्ज किया गया। डीसीपी पूर्वी जिला राजीव कुमार के मुताबिक, पुलिस ने ई-रिक्शा के पंजीकरण नंबर के आधार पर उसके मालिक कल्याणपुरी निवासी 55 वर्षीय अंसार का पता लगाया। पूछताछ में सामने आया कि ई-रिक्शा उनका बेटा जुबैर चलाता है। जांच में यह भी पता चला कि जुबैर और उसके बहनोई नजरे आलम के खिलाफ पहले भी सनलाइट कॉलोनी थाने में लूट का मामला दर्ज है। पुलिस ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। 20 नवंबर को जुबैर को तुर्कमान गेट इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसके अगले दिन 21 नवंबर को नजरे आलम को लाजपत नगर अंडरपास के पास से पकड़ा गया। बाद में नजरे आलम की पत्नी मुस्कान और जुबैर की मां इशरत को भी लाजपत नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उनके साथ दो नाबालिग बच्चे भी मौजूद थे।



पुलिस ने वारदात के दौरान ई-रिक्शा के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें ई-रिक्शा के अगले हिस्से में लाल स्वेटर पहने एक पुरुष और नीले सूट में एक महिला दिखाई दिए। पुलिस के अनुसार, फुटेज में दिख रहे कपड़े गिरफ्तारी के समय नजरे आलम और मुस्कान के पहने कपड़ों से मेल खाते थे। जांच में आशंका जताई जा रही है कि परिवार के कई सदस्य मिलकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे और महिलाओं व बच्चों की मौजूदगी का इस्तेमाल पुलिस और यात्रियों को शक से बचाने के लिए करते थे। पुलिस ने जुबैर की निशानदेही पर कल्याणपुरी स्थित एक मकान से वारदात में इस्तेमाल चाकू, पीड़ित राजेश का आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र और 710 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, जुबैर और नजरे आलम पहले भी सनलाइट कॉलोनी थाने में दर्ज लूट के एक मामले में शामिल रहे हैं। पुलिस अब चारों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस तरीके से अन्य वारदातों को तो अंजाम नहीं दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

एक नजर

शादी से इनकार पर महिला का गला रेता, हालत नाजुक

साहिबाबाद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में टीला मोड़ थना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने महिला के गले को धारदार हथियार से रेत दिया। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं, घटना के बाद आरोपी ने भी नशे की हालत में छत से छलांग लगा दी। इस घटना में वह भी घायल हुआ है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। नोएडा निवासी अब्दुल रहमान का कहना है कि उनकी 35 वर्षीय बहन खुशबू अपने पति से अलग बेटी के साथ अंबेडकर कॉलोनी में किराये पर रहती हैं। पड़ोस में रहने वाला जगदेव नशे का आदी है और उनकी बहन को परेशान करता है। वह अक्सर बहन पर शादी का दबाव बनाता है। सोमवार दोपहर उनकी खुशबू अपनी बेटी के साथ बाजार जा रही थी। इस दौरान जगदेव नशे की हालत में आया और शादी का दबाव बनाया। खुशबू के मना करने पर उसने धारदार हथियार से खुशबू के गले पर वार कर दिया। खुशबू ने घायल होने पर शोर मचाया तो आरोपी भाग कर पड़ोस की छत पर चढ़ गया। आसपास के लोगों ने उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद आरोपी नशे की हालत में छत से कूद गया। इससे उसके हाथ में फ्रेक्चर आया और कमर में चोट है। पुलिस ने उसे अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। महिला की हालत अस्पताल में सामान्य है। आरोपी के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

18 करोड़ खर्च, फिर भी जहरीली हवा से राहत नहीं

साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जिले में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए एक्यूआई मानिटरिंग स्टेशनों की संख्या लगातार जरूर बढ़ती गई, लेकिन इसका जमीन पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। 7 माह पहले तक केवल वसुंधरा, इंदिरापुरम, संजय नगर व लोनी में ही प्रदूषण मापक यंत्र लगे थे, लेकिन अब डासना देहात, न्यू तहसील लोनी, गोविंदपुरम, वेव सिटी, वेद विहार व खोड़ा में भी एक्यूआई मॉनिटरिंग सिस्टम लग गए हैं। यूपीपीसीबी के अधिकारियों की मानें तो सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) ने प्रत्येक मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाने पर करीब तीन करोड़ का बजट खर्च किया है। यानी छह स्टेशनों पर 18 करोड़ का बजट खर्च किया गया है। वहीं, इससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पीएम (पार्टिकुलेट मैटर)-2.5, पीएम-10 समेत हवा में अन्य जहरीले तत्वों के सटीक आंकड़े जरूर मिल रहे हैं, लेकिन जमीं पर कोई भी ठोस योजना दिखाई नहीं दे रही है। दैनिक जागरण की पड़ताल में खुले में पड़ी निर्माण सामग्री, जगह-जगह जलता कूड़ा, सड़कों पर उड़ती धूल, औद्योगिक इकाइयों से निकलता जहरीला धुआं, मुख्य सड़कों पर वाहनों का दबाव समेत तमाम प्रदूषण के ऐसे कारक मिले, जो अधिकारियों के प्रदूषण रोकने के दावों की पोल खोलते नजर आए।

शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी

नोएडा। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर नोएडा में शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने की लालच देकर अज्ञात साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति से 11 लाख रुपये की ठगी कर ली। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि विजय कुमार श्रीवास्तव ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एक अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करने के बहाने कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया तथा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर मोटा मुनाफा कमाने की लालच दिया। आरोपितों ने उन्हें एक लिंक भेजा। उन्होंने कहा कि इसपर शेयर खरीदने और बेचने के सारे फीचर्स हैं। पीड़ित ने भेजे गए लिंक के प्लेटफार्म को चेक करने के बहाने थोड़ी रकम ट्रांसफर करने की बात कही। पीड़ित ने 10 रूपये ट्रांसफर किए। उन्होंने आरोपितों की बात में आकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर विभिन्न बार में 11 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया।

गाजियाबाद में 12 और 45 मीटर चौड़ी बनेंगी सड़कें

गाजियाबाद। गाजियाबाद में हरनंदीपुरम आवासीय योजना को विकसित की दिशा में प्राधिकरण ने एक कदम और बढ़ाया है। योजना के पहले चरण में सड़क और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 60.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 12 और 45 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण से संबंधित दो टेंडर जारी किए गए हैं। वहीं, योजना में प्रस्तावित 18 होल के अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स की डीपीआर तैयार कराने के लिए भी सलाहकार चयन की प्रक्रिया शुरू की है। प्राधिकरण की ओर से जारी पहले टेंडर के तहत 12 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 13 करोड़ 12 लाख 31 हजार 812 रुपये खर्च होंगे। सड़क के साथ सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन और ड्रेनेज की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए नौ माह की समयसीमा निर्धारित की है। इसके अलावा 45 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण पर 47 करोड़ 58 लाख 44 हजार 33 रुपये खर्च होंगे। सड़क निर्माण के साथ केबल डक्ट, डिवाइडर, सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेन और पार्क विकसित किए जाएंगे।

18वीं राष्ट्रीय युवा संसद में युवाओं ने किया जीवंत प्रदर्शन



गुरुग्राम, एजेंसी। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जन-जागरुकता बढ़ाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाए। यही भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह बात राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बुधवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड एलाइड स्टडीज (सीपीएएस) गुरुग्राम में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद में कही।

राष्ट्रीय संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर इस युवा संसद का आयोजन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया। युवा संसद के समापन पर निर्णायक मंडल ने छह विद्यार्थियों मेगन, अंशिका, अक्ष, मोहम्मद जुनेद, कार्तिकेय शुक्ला और संदीप भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ छह वक्ताओं के रूप में घोषित किया। मुख्य अतिथि सुभाष बराला ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप लैंगिक समानता, सामाजिक समरसता और समावेशी समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा मॉडल संसद की प्रभावशाली प्रस्तुति और संसदीय कार्यवाही के जीवंत प्रदर्शन की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एमडीयू के कुलपति प्रो. मिलाप पूनिया ने कहा कि भारतीय संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित भारत का विजन प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों एवं युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि वे संवैधानिक मूल्यों को अपने आचरण का आधार और राष्ट्रसेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। कुलपति ने युवाओं से जागरूक नागरिक, जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता और भारतीय लोकतंत्र के गौरवशाली प्रतिनिधि बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के सदस्य डॉ. करमबीर गिल तथा युवा संसद की ग्रुप कोऑर्डिनेटर डॉ. शालिनी शर्मा ने भी अपने विचार सांझा किए। एमडीयू-सीपीएएस की निदेशक प्रो. कविता ढुल ने स्वागत भाषण दिया। राष्ट्रीय युवा संसद के संयोजक प्रो. अनुपम कुरवाल ने मॉडल युवा संसद की अवधारणा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला। डॉ. विजय राठी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बिना इंजन चालू किए और धुआं जांचें बांट रहे पीयूसीसी

गाजियाबाद। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वाहनों की पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) जांच अनिवार्य है, लेकिन जिले में इस व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले में संचालित 250 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्रों में कुछ पर वाहनों को लाए बिना ही प्रमाणपत्र जारी करने का खेल चल रहा है। कहीं केवल नंबर प्लेट की फोटो और वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी से पीयूसी बनवाने की सुविधा दी जा रही है, तो कहीं इंजन चालू किए बिना ही जांच की औपचारिकता पूरी की जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से केंद्रीय पीयूसी पोर्टल के ट्रांजेक्शन का विश्लेषण करने पर प्रदेश के 83 प्रदूषण जांच केंद्रों में अनियमितता की आशंका जताई गई थी। इनमें गाजियाबाद के 32 केंद्र शामिल हैं। इससे पहले भी पोर्टल पर तीन मिनट से कम समय में बड़ी संख्या में प्रमाणपत्र जारी होने के आधार पर जिले के 36 केंद्र चिह्नित किए गए थे। परिवहन विभाग ने कुछ केंद्रों के पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति भी शासन को भेजी है। मंगलवार को विभिन्न केंद्रों की पड़ताल में पीयूसी जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही सामने आई। नियमानुसार वाहन के साइलेंसर में सेंसर प्रोब पाइप लगाकर इंजन चालू अवस्था में उत्सर्जन की जांच करना जरूरी है। इसके बाद ही निर्धारित मानकों के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। इसके बावजूद कुछ केंद्रों पर बिना वाहन की मौजूदगी के ही प्रमाणपत्र जारी करने की बात कही जा रही है।

नूंह पुलिस ने छह माह में गोकशी के 218 मुकदमे दर्ज कर 385 आरोपी किए गिरफ्तार



नूंह। नूंह जिले में गोकशी के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नूंह पुलिस ने इस साल बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 अप्रैल से 28 अक्टूबर तक गोकशी से जुड़े 218 मुकदमे दर्ज कर 385 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अपराध में संलिप्त 130 वाहनों को जब्त करने के साथ 533 गोवंश को मुक्त कराया गया है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में पुलिस की कार्रवाई के आंकड़ों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पुलिस अधीक्षक नूंह डॉ. अर्पित जैन ने के निर्देशानुसार गोकशी के अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस की विभिन्न टीमों ने लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की और गोकशी से जुड़े वाहनों को जब्त किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक जिले में गोकशी के 90 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस दौरान 303 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 62 वाहन जब्त किए गए और 320 गोवंश को मुक्त कराया गया था। वहीं, इस वर्ष 4 अप्रैल से 28 अक्टूबर तक 218 मुकदमे दर्ज किए गए, 385 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, 130 वाहन जब्त किए गए और 533 गोवंश को मुक्त कराया गया। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष दर्ज मुकदमों, गिरफ्तार आरोपियों, जब्त वाहनों और मुक्त कराए गए गोवंश की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन ने स्पष्ट किया कि गोकशी जैसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में इस अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार घटी, आज से अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे



नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से वाहनों की गति सीमा घटा दी गई है। चालक अधिकतम 75 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चला सकते हैं। पहले यह सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर इससे ज्यादा गति से वाहन चलाया तो चालान होगा। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आर के सिंह ने बुधवार को बताया कि इससे पूर्व 15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा कम की जाती थी, लेकिन इन दिनों ठंड और धुंध अधिक रहने के चलते 25 नवंबर से ही गति सीमा घटाने का निर्णय किया है। यह व्यवस्था 15 फरवरी तक लागू रहेगी।

वहीं, एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के इंतजाम भी दुरुस्त किए गए हैं। उन्होंने वाहन चालकों से अपील किया कि वे नियमों का पालन करें अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही, यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्रबंधक जेके शर्मा ने बताया कि कि ठंड और धुंध के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग के लिए 24 टीमें तैनात की गई हैं। घायलों को समय से अस्पताल पहुंचने के लिए सात एंबुलेंस और वाहन हटाने के लिए 12 क्रेन भी तैनात की गई हैं। उन्होने बताया कि दुर्घटना होने पर घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए समय सारिणी और फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया गया है। ओवर लोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जीरो प्वाइंट से जेवर टोल पर दोनों तरफ विशेष टीमें तैनात की गई हैं। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग के लिए 24 गाड़ियों लगाई गई हैं। इन वाहनों से एक्सप्रेसवे के दोनों तरह पेट्रोलिंग कर व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। वहीं, दोनों तरह छह-छह क्रेन तैनात की गई हैं, ताकि हादसा होने पर वाहनों को हटाकर आवागमन व्यवस्थित किया जा सके। वाहनों में आगजनी की घटना पर आठ फायर की गाड़िया भी नियुक्त की गई हैं। वाहनों पर रिफलेक्टर टेप चिपकाने के लिए अभियान शुरू किया गया है।

फरीदाबाद : होटल में युवती की मौत का मामला हत्या में बदला, फरार प्रेमी की तलाश में जुटी पुलिस



फरीदाबाद। सेक्टर-37 स्थित होटल में दिल्ली विश्वविद्यालय की 19 वर्षीय छात्रा अरुणा की मौत के मामले में पुलिस की जांच हत्या की ओर मुड़ गई है। होटल के कमरे से मिले दो हस्तलिखित नोट में युवती के प्रेमी विपिन यादव ने आठ साल पुराने प्रेम संबंधों का जिक्र करते हुए अरुणा की हत्या के बाद खुद भी जान देने की बात लिखी है। हालांकि, पुलिस अभी मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। पुलिस के अनुसार, कुरैशीपुर गांव निवासी अरुणा और विपिन 23 नवंबर को सेक्टर-37 स्थित होटल जोया पहुंचे थे।

दोनों ने होटल में कमरा नंबर 204 बुक कराया था। होटल की सीसीटीवी फुटेज में विपिन सोमवार शाम कमरे से बाहर निकलता दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। मंगलवार दोपहर होटल कर्मचारियों ने कमरा खुलवाया तो अरुणा मृत अवस्था में मिली। कमरे से चूहे मारने की दवा के खाली रैपर भी बरामद हुए हैं। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कमरे से विपिन के हस्ताक्षर वाले दो नोट मिले। एक नोट में उसने अरुणा के साथ आठ साल से प्रेम संबंध होने का उल्लेख करते हुए उसकी हत्या के बाद आगरा नहर में कूदकर खुद भी जान देने की बात लिखी है। दूसरे नोट में कई लोगों के साथ लाखों रुपये के लेन-देन का हिसाब दर्ज है। परिजनों ने शव की पहचान अरुणा के रूप में की। पुलिस अब फरार विपिन की तलाश में जुटी है। मामले की जांच कर रहे धौज थाना प्रभारी अनिल कुमार के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम के बाद ही अरुणा की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। कमरे से चूहे मारने की दवा के रैपर मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि युवती को यही दवा दी गई थी। अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस विपिन की तलाश कर रही है। नोट में आगरा नहर में कूदने की बात लिखे जाने के बाद, वहां भी पुलिस टीम भेजी गई है। टीम नहर में उसकी तलाश कर रही है। इसके अलावा होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

19वीं मंजिल से कूदकर 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोयडा थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में रहने वाली एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने आज तड़के अपनी सोसाइटी के 19वीं मंजिल स्थित फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सेक्टर -39 के प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ल ने बताया कि सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में रहने वाले अभिनव दुबे की 16 वर्षीय बेटी डिशिता दुबे ने 19वीं मंजिल स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से मंगलवार सुबह 3 बजे के करीब छलांग लगा दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला की मृतका के परिजनों ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया था। इस बात से वह परेशान थी। वह एक नामी स्कूल से 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के पिता एडीडास कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

गोद लिए स्कूलों का क्लास 1-2 अफसरों को करना होगा निरीक्षण

गुरुग्राम। सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अब प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सीधे उनकी एसीआर से जुड़ जाएगी। अपनी एसीआर को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को साल में कम से कम तीन बार गोद लिए गए स्कूलों का दौरा करना होगा। अगर निरीक्षण किए बिना ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो वह अधूरी मानी जाएगी।

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश दिए हैं कि क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में उनके द्वारा गोद लिए गए स्कूलों, स्कूलों के दौरों और निरीक्षणों का विवरण दर्ज करने के लिए एक विशेष कॉलम जोड़ा जाएगा। एसीआर में जोड़े जाने वाले विशेष कॉलम में अधिकारी द्वारा गोद लिए गए स्कूल का नाम, वहां किए गए दौरों की संख्या और निरीक्षण के दौरान की गई समीक्षा का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों को अपनी वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गोद लिए गए स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत करें, शिक्षण गतिविधियों की स्थिति समझें, उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग की समीक्षा करें तथा सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें। उन्होंने कहा कि इस पहल का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्कूल अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप बेहतर ढंग से कार्य करे। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूलों का निरीक्षण निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार किया जाए और निरीक्षण के दौरान सामने आए तथ्यों एवं सुझावों को उचित रूप से दर्ज किया जाए, ताकि उन पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि एसीआर में निरीक्षण संबंधी विवरण शामिल करने से प्रशासनिक जिम्मेदारी और स्कूलों के वास्तविक सुधार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।

नूंह के गांवों में शराब ठेकों के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, डीसी को सौंपा ज्ञापन

नूंह। नूंह जिले के गांव कुरथला और आलदोका में शराब के ठेकों और कथित तौर पर बढ़ती नशाखोरी को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज होने लगा है। दोनों गांवों के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला उपायुक्त अखिल पिलानी को ज्ञापन सौंपकर गांवों में शराब के ठेके हटाने और नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि स्कूल, मंदिर और गांव की फिरनी के इतने नजदीक शराब का ठेका संचालित करने की अनुमति कैसे दी गई।

ग्रामीणों के अनुसार, कुरथला गांव में शराब का ठेका स्कूल, मंदिर और गांव की फिरनी से 100 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इस संबंध में पहले भी गांव में पंचायत आयोजित कर ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूछा कि जब गांव के लोग एकजुट होकर ठेका हटाने की मांग कर रहे हैं तो उनकी शिकायत पर समाधान क्यों नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने गांवों में शराब के ठेकों के अलावा चिट्टा, गांजा, सूखा नशा और अवैध शराब की कथित बिक्री पर भी चिंता जताई। उनका आरोप है कि गांवों में नशे का प्रभाव किशोरों तक पहुंच रहा है और 13 से 17 वर्ष तक के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यह उम्र बच्चों के पढ़ने-लिखने और खेलकूद में आगे बढ़ने की है, लेकिन नशे की बढ़ती प्रवृत्ति उनके भविष्य के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की कि कुरथला और आलदोका गांवों से शराब के ठेकों को तत्काल हटाकर आबादी से बाहर शिफ्ट किया जाए। यदि तत्काल ठेका हटाना संभव नहीं है तो इसे कम से कम आबादी से दो किलोमीटर दूर स्थापित किया जाए। साथ ही आगामी आबकारी नीति में दोनों गांवों को शराब के ठेकों से मुक्त रखने का प्रावधान किया जाए। ग्रामीणों ने कथित तौर पर बिक रहे सूखे नशे और अवैध शराब के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने की मांग की। जिला उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आगामी आबकारी नीति में शराब के ठेके हटाने की उनकी मांग पर विचार किया जाएगा।

केमिकल सेफ्टी टैंक हादसे में पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे कंपनी



गुरुग्राम। गुरुग्राम में 11 नवंबर को भौंडसी स्थित एक कंपनी के केमिकल सेफ्टी टैंक में जांच के दौरान तीन कर्मचारियों की हुई मृत्यु के मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य डॉ. सुषमा गोरियाल ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने संबंधित कंपनी के परिसर में पहुंचकर हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कंपनी प्रबंधन और मृतक कर्मचारियों के परिजनों के साथ संयुक्त बैठक कर पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की तथा पीड़ित परिवारों को न्याय एवं नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए।

डॉ. सुषमा गोरियाल ने कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना करते हुए मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को निर्धारित मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के तहत पात्र मृतक सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसलिए मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कंपनी अपने सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करे। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले में पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने तथा जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य डॉ. सुषमा गोरियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज और शहर की स्वच्छता व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी संबंधित अधिकारी सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

महिलाओं की भय-हिंसा मुक्ति से ही विकसित भारत संभव

ललित गर्ग



महिला हिंसा केवल किसी एक महिला के साथ हुआ अपराध नहीं है, यह पूरी मानवता की चेतना पर लगा हुआ घाव है। किसी महिला का घर में अपमानित होना, दहेज के लिए प्रताड़ित होना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न सहना, सड़क पर असुरक्षित महसूस करना, यौन हिंसा का शिकार होना या डिजिटल माध्यमों से उसकी निजता और गरिमा को चोट पहुंचाना-इनमें से हर घटना समाज की उस मानसिकता को उजागर करती है, जिसमें स्त्री को बराबरी का मनुष्य मानने की भावना अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस इसलिए केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन और सामाजिक संकल्प का दिन है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला 16 दिवसीय अभियान हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करना केवल कानून और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह परिवार, समाज, पुरुष, संस्थाओं, न्याय-व्यवस्था और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र की 2026 की थीम-महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट हों, न्याय सुनिश्चित करें, पीड़ितों की सुरक्षा करें, और दोषियों को सजा से बचने न दें-का मूल संदेश स्पष्ट है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों एवं हिंसा पर नियंत्रण हो, न्याय सुनिश्चित हो, पीड़ितों की सुरक्षा हो और अपराधियों को दंड से बचने की संस्कृति समाप्त हो। सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर ही नारी-मुक्ति का वास्तविक रास्ता है, इसी से विकसित भारत संभव है।

आज दुनिया ने महिला हिंसा के अनेक पुराने चेहरों को पहचान लिया है, लेकिन हिंसा ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार के साथ अब साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन धमकी, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, डिजिटल निगरानी और कार्यस्थल पर मानसिक दबाव जैसी नई चुनौतियां सामने हैं। इसलिए महिला सुरक्षा की लड़ाई केवल पुलिस थाने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे घर की मानसिकता, विद्यालय की शिक्षा, कार्यस्थल की संस्कृति और डिजिटल व्यवहार तक ले जाना होगा। भारत में स्थिति जटिल भी है और परिवर्तनशील भी। एक ओर महिलाएं राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, शिक्षा, सेना, खेल, उद्योग और उद्यमिता में नई ऊंचाइयां छू रही हैं, दूसरी ओर अनेक महिलाएं आज भी हिंसा, भेदभाव, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक दबाव के घेरे में हैं। कानूनों की कमी से अधिक समस्या कई बार उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक चुप्पी और पीड़िता को ही दोषी मानने वाली मानसिकता की होती है। महिला को यह समझाना आवश्यक है कि उसके साथ हुई हिंसा उसकी गलती नहीं है। अपराधी का अपराध अपराधी का ही है, पीड़िता को अपराधबोध में जीने के लिए मजबूर करना दूसरी हिंसा है। मीटू जैसे आंदोलनों और निर्भया कांड के बाद हुए कानूनी सुधारों ने समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव पैदा किया है। पहले जिस हिंसा को 'घर की बात', 'इज्जत का मामला' या 'समझौते से सुलझाने' की सलाह देकर दबा दिया जाता था, उसके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस बढ़ा है। लेकिन आवाज उठाना पहला कदम है, अंतिम समाधान नहीं। शिकायत करने वाली महिला को सुरक्षा, सम्मान, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सहयोग और त्वरित न्याय मिले, तभी कानून पर उसका विश्वास मजबूत होगा। हमें यह भी समझना होगा कि हिंसा का वास्तविक अंत अदालत के फैसले से पहले मानसिकता के परिवर्तन से शुरू होता है। जिस घर में बेटे को अधिकार और बेटी को मर्यादा का पाठ अलग-अलग पढ़ाया जाता है, वहां समानता की नींव कमजोर रहती है। बेटे को यह सिखाना होगा कि स्त्री उसकी संपत्ति नहीं, स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसकी सहमति सर्वोपरि है। प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान है और पुरुषत्व का अर्थ प्रभुत्व नहीं, संवेदनशीलता है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी हिंसा के विरुद्ध एक प्रभावी कवच है। जो महिला शिक्षित है, आर्थिक रूप से सक्षम है, अपने अधिकारों से परिचित है और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकती है, उसके लिए हिंसक परिस्थितियों से बाहर निकलने की संभावना अधिक होती है। इसलिए भारत में 'पहुँच से सशक्तिकरण तक विकसित भारत के लिए आजीविका और समान अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' जैसी सोच अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इकनोमिक फोरम कि स्थिति बताती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो महिलाएँ लगभग बराबरी के स्तर तक पहुँच गई हैं, परंतु आर्थिक अवसरों और राजनीतिक नेतृत्व में अभी भी उनकी भागीदारी सीमित है। वैश्विक स्तर पर महिलाएँ कुल कार्यबल का लगभग 42 प्रतिशत ही हैं और शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर उनकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई के आसपास है। भारत में भी स्थिति मिश्रित है। विकसित भारत का सपना तभी सार्थक होगा, जब उसकी आधी आबादी भय से मुक्त होकर अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके। हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कैमरे, कानून और हेल्पलाइन नहीं, बल्कि सुरक्षित संस्कारों का वातावरण बनाना होगा। विद्यालयों में लैंगिक सम्मान और संवेदनशीलता की शिक्षा हो, परिवारों में बेटियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले, कार्यस्थलों पर शिकायत तंत्र निष्पक्ष और प्रभावी हो तथा पुलिस और न्याय-व्यवस्था पीड़िता के प्रति संवेदनशील बने। मीडिया और सोशल मीडिया को भी सनसनी के बजाय गरिमा और जिम्मेदारी का रास्ता चुनना होगा। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन पुरुष समाज में होना है।

स्त्री के प्रति हिंसा की जड़ में केवल अपराधी प्रवृत्ति नहीं, बल्कि वह सोच भी है जो स्त्री को कमजोर, भोग की वस्तु या पुरुष के नियंत्रण का विषय समझती है। पुरुषत्व को प्रभुत्व से करुणा, अधिकार से उत्तरदायित्व और शक्ति से संरक्षण की ओर मोड़ना होगा। पुरुष यदि महिला की स्वतंत्रता को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, उसकी मानवीय गरिमा का अधिकार समझेगा, तभी परिवर्तन स्थायी होगा। नये युग की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और डिजिटल असमानता भी महिलाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। यदि इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दशकों में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी की ओर धकेली जा सकती हैं। इतिहास के पन्ने यह भी बताते हैं कि जब-जब समाज संकट में पड़ा, तब-तब नारी शक्ति ने असाधारण साहस का परिचय दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा उन्हें गैस सिलिंडर दिलाना हो, गावों में घरों और शौचालय का निर्माण हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास कराना। आज दुनिया के सभी देश इस बात को मान रहे है की मोदी के नेतृत्व में भारत की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। खेल जगत से लेकर मनोरंजन जगत तक और राजनीति से लेकर सैन्य व रक्षा तक में महिलाएं बड़ी भूमिका में हैं। बात भारतीय या अभारतीय नारी की नहीं, बल्कि उसके प्रति दृष्टिकोण की है। आवश्यकता इस दृष्टिकोण को बदलने की है, जरूरत सम्पूर्ण विश्व में नारी के प्रति उपेक्षा एवं प्रताड़ना को समाप्त करने की है। इस दिवस की सार्थकता तभी है जब महिलाओं को विकास में सहभागी ही न बनाये बल्कि उनके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौंचने की वीभत्सताओं एवं त्रासदियों पर विराम लगे, ऐसा वातावरण बनाये। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस हमें एक बड़ा संकल्प देता है-ऐसा समाज बनाने का, जहां महिला को अपनी सुरक्षा के लिए हर समय संघर्ष न करना पड़े, जहां बेटी को जन्म लेने से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक भय के बजाय सम्मान मिले, जहां न्याय पाने के लिए उसे अपनी पीड़ा बार-बार सिद्ध न करनी पड़े और जहां बलात्कार, दहेज-हिंसा, छेड़छाड़, उत्पीड़न और स्त्री-अस्मिता के अपमान जैसे शब्द धीरे-धीरे इतिहास के शब्दकोश का हिस्सा बन जाएं। महिला हिंसा का अंत केवल महिलाओं को सुरक्षित करने का अभियान नहीं है, यह पुरुषों को अधिक मानवीय और समाज को अधिक सभ्य बनाने का अभियान है। जिस दिन किसी महिला को अपनी गरिमा बचाने के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि समाज स्वयं उसकी गरिमा का प्रहरी बन जाएगा, उस दिन इस दिवस की सार्थकता पूरी होगी। नारी को दया नहीं, न्याय चाहिए। संरक्षण मात्र नहीं, समान अवसर चाहिए। सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए। क्योंकि जिस समाज में उसकी आधी आबादी भयमुक्त नहीं है, वह समाज वास्तव में विकसित नहीं हो सकता।

इस परियोजना की खासियत यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सिंगल-सेल एनालिसिस जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. देबार्का सेनगुप्ता, जो आईआईआईटीडी-दिल्ली में इनोवेशन, रिसर्च एवं डेवलपमेंट के एसोसिएट डीन भी हैं, के अनुसार इस किट से होने वाली जांच कैंसर की पहचान और उसके इलाज की योजना तैयार करने में मददगार हो सकती है। इसका उद्देश्य केवल बीमारी का पता लगाना नहीं, बल्कि मरीज के लिए आगे की जांच और उपचार की दिशा तय करने में चिकित्सकों को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना है। दरअसल शोधकर्ताओं ने एआई आधारित ऐसा ब्लड टेस्ट विकसित किया है, जो कई प्रकार के कैंसर की अपेक्षाकृत किफायती स्क्रीनिंग में मदद कर सकता है। इस तकनीक का महत्वपूर्ण पहलू इसका 11-जीन वाला ब्लड टेस्ट है, जो प्लेटलेट आरएनए पर आधारित है। इसमें रियल टाइम पीसीआर (आरटी-पीसीआर) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए रक्त में मौजूद विशेष जैविक संकेतों और जीन से संबंधित बदलावों का विश्लेषण कर कैंसर की आशंका को पहचानने में मदद मिल सकती है। कैंसर की पहचान के लिए शरीर में होने वाले सूक्ष्म जैविक बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। कई बार बीमारी के शुरुआती चरण में स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। मरीज को तब तक अपनी परेशानी का अंदाजा नहीं होता, जब तक बीमारी काफी आगे न बढ़ जाए। ऐसे में रक्त के नमूने के माध्यम से कैंसर से जुड़े संकेतों की पहचान करने वाली तकनीक चिकित्सा जगत के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, स्क्रीनिंग में किसी संभावित संकेत का मिलना अंतिम निदान नहीं माना जाएगा। इसकी पुष्टि के लिए चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक अतिरिक्त जांच जरूरी होगी।

अब यदि इसी व्यवस्था का इस्तेमाल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जा सके तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हर जगह नई और महंगी मशीनें लगाने की आवश्यकता कम होगी। मौजूदा प्रयोगशालाओं को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार करके जांच का दायरा बढ़ाया जा सकेगा। इससे छोटे शहरों और कस्बों तक कैंसर की जांच सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिल सकती है। एआई की भूमिका भी इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बड़ी मात्रा में प्राप्त जैविक और जीन संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे पैटर्न पहचानने में मदद कर सकता है, जिन्हें सामान्य तरीके से समझना कठिन हो सकता है। इससे जांच के परिणामों का आकलन करने और चिकित्सकों को निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, तकनीक की वास्तविक उपयोगिता उसकी वैज्ञानिक पुष्टि, सटीकता, संवेदनशीलता और विभिन्न आबादी पर किए गए परीक्षणों के परिणामों से ही तय होगी। यह भी जरूरी है कि ऐसी किसी भी नई जांच तकनीक को व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने से पहले उसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का पर्याप्त वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए। अलग-अलग प्रकार के कैंसर की जैविक प्रकृति अलग होती है। कुल मिलाकर, केयरओन्को बायोटेक की यह पहल भारत में कैंसर की शुरुआती पहचान को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक संभावनाशील प्रयास है। कोविड महामारी के दौरान तैयार हुआ आरटी-पीसीआर ढांचा अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ाई में भी उपयोगी साबित हो सकता है। विज्ञान और तकनीक का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उसका लाभ आम आदमी तक पहुंचे। यदि यह नई जांच तकनीक अपने वैज्ञानिक दावों पर खरी उतरती है और व्यापक स्तर पर उपलब्ध होती है तो कैंसर के खिलाफ भारत की लड़ाई को नई ताकत मिल सकती है। बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए समय पर पहचान की सुविधा किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी।

कैंसर के खिलाफ जंग में अब एआई का साथ

विवेक शुक्ला

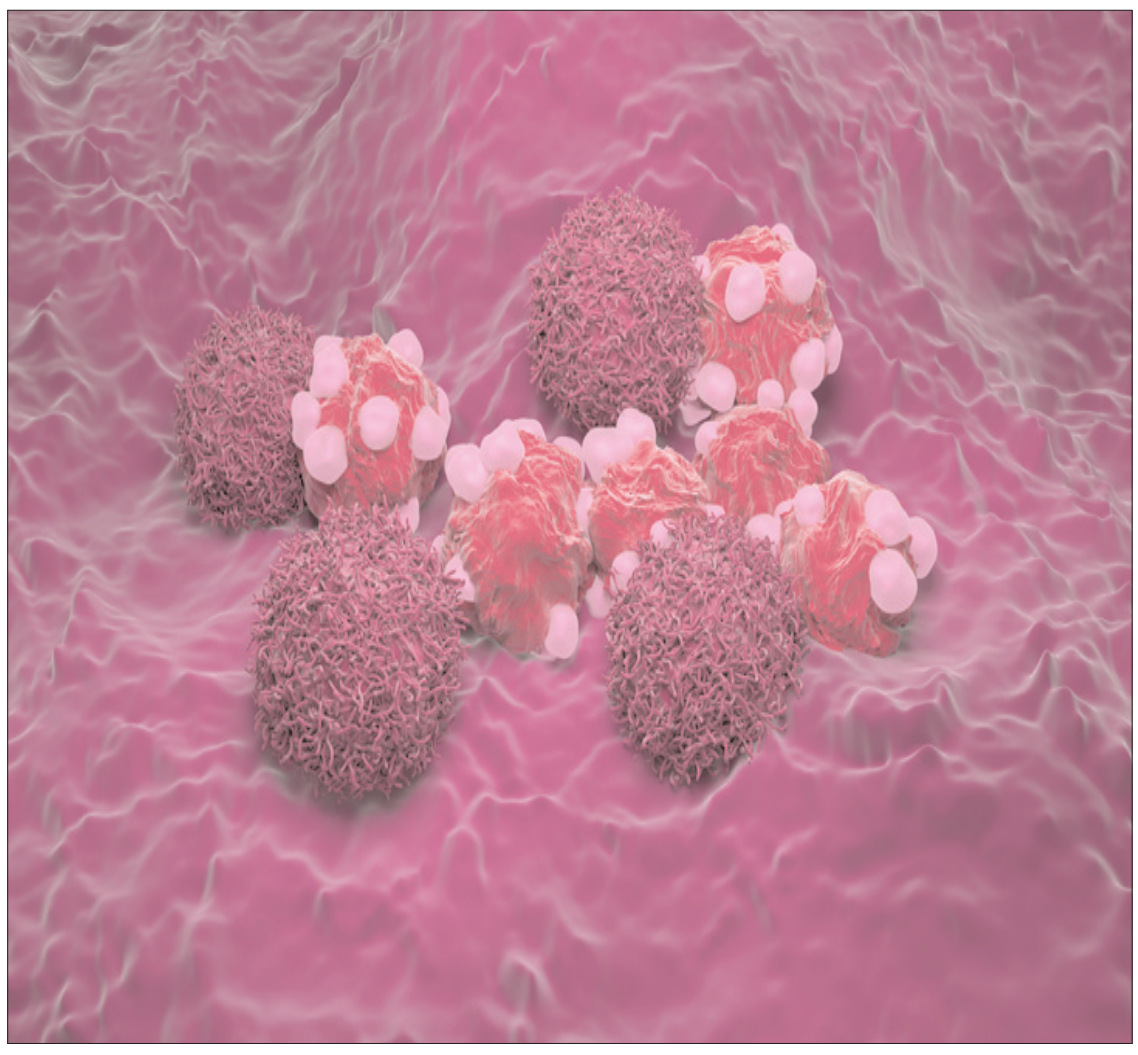

कैंसर आज दुनिया की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। इस बीमारी से लड़ाई में अहम बात यह है कि समय रहते इसकी पहचान। यदि कैंसर का शुरुआती अवस्था में पता चल जाए तो इलाज की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में कैंसर की समय पर जांच आज भी बड़ी चुनौती है। जांच का खर्च, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की सीमित उपलब्धता और बीमारी के प्रति जागरूकता का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से विकसित की जा रही एक नई ब्लड टेस्ट तकनीक उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है।

हैदराबाद स्थित केयरओन्को बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को कैंसर की पहचान के लिए एआई आधारित मेडिकल किट बनाने का एमडी-13 लाइसेंस केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से मिलना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी इस तकनीक के माध्यम से ऐसी जांच सुविधा विकसित करने की तैयारी में है, जिससे शरीर में कैंसर से जुड़े शुरुआती जैविक संकेतों का पता लगाने में मदद मिल सके। कंपनी हैदराबाद में अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित कर रही है। भारत में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की बड़ी आबादी को समय पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। अक्सर लोग बीमारी के लक्षण गंभीर होने के बाद ही अस्पताल पहुंचते हैं। यदि कम खर्च में स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध होती है तो अधिक लोग समय रहते जांच कराने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इससे बीमारी की आशंका वाले लोगों की पहचान कर उन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए भेजना आसान हो सकता है। इस परियोजना की खासियत यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सिंगल-सेल एनालिसिस जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. देबार्का सेनगुप्ता, जो आईआईआईटीडी-दिल्ली में इनोवेशन, रिसर्च एवं डेवलपमेंट के एसोसिएट डीन भी हैं, के अनुसार इस किट से होने वाली जांच कैंसर की पहचान और उसके इलाज की योजना तैयार करने में मददगार हो सकती है। इसका उद्देश्य केवल बीमारी का पता लगाना नहीं, बल्कि मरीज के लिए आगे की जांच और उपचार की दिशा तय करने में भी चिकित्सकों को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना है। दरअसल शोधकर्ताओं ने एआई आधारित ऐसा ब्लड टेस्ट विकसित किया है, जो कई प्रकार के कैंसर की अपेक्षाकृत किफायती स्क्रीनिंग में मदद कर सकता है। इस तकनीक का महत्वपूर्ण पहलू इसका 11-जीन वाला ब्लड टेस्ट है, जो प्लेटलेट आरएनए पर आधारित है। इसमें रियल टाइम पीसीआर (आरटी-पीसीआर) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए रक्त में मौजूद विशेष जैविक संकेतों और जीन से संबंधित बदलावों का विश्लेषण कर कैंसर की आशंका को पहचानने में मदद मिल सकती है। कैंसर की पहचान के लिए शरीर में होने वाले सूक्ष्म जैविक बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। कई बार बीमारी के शुरुआती चरण में स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। मरीज को तब तक अपनी परेशानी का अंदाजा नहीं होता, जब तक बीमारी काफी आगे न बढ़ जाए। ऐसे में रक्त के नमूने के माध्यम से कैंसर से जुड़े संकेतों की पहचान करने वाली तकनीक चिकित्सा

विचार

लतीफ भट के बाद कश्मीर में स्थाई शांति की आहट

विक्रम उपाध्याय

कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी मोहम्मद लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर में अब कोई सक्रिय स्थानीय आतंकवादी नहीं बचा है। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आतंकवाद का दंश कश्मीर 35 वर्षों से झेल रहा है, लेकिन अब कह सकते हैं कि वहां अब शांति का एक अहसास स्थानीय लोग महसूस कर रहे हैं। लगभग चार दशक बाद यह बात सुकून देने वाली है कि इस समय कोई अपना कश्मीरी बच्चा देश के खिलाफ जेहाद के रास्ते पर नहीं है। इसके लिए मोदी सरकार, खासकर गृहमंत्री अमित शाह को शाबाशी मिलनी चाहिए। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार किया और देश के खिलाफ जेहाद करने वालों को 'जहां भी हों खत्म करो' की नीति को मजबूती से लागू किया। आतंकवाद के खिलाफ आम कश्मीरियों में भी वितृष्णा देखी जा रही है। खासकर युवाओं में देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की नई प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है। मोदी सरकार भी उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दे रही है। अकेले 2026 में पूरे कश्मीर से 500 से अधिक युवाओं ने अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती ली है। यह बदलते कश्मीर की एक झलक है। हाल ही में एनआईए के आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में गृहमंत्री ने कहा भी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में स्थायी सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो। खुफिया जानकारी साझा हो और स्पष्ट जवाबदेही भी हो। वास्तव में कश्मीर घाटी से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट का खात्मा इसी समन्वय का परिणाम है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। 35 वर्षों में पहली बार कश्मीर में कोई भारतीय सक्रिय आतंकवादी नहीं है। भारत की यह धरती लोकल आतंकवादी जैसे दोषपूर्ण नाम से मुक्त हो गई है।

बकौल गृहमंत्री इस समय देश भर से 40 से अधिक आतंकवादी मॉड्यूल्स को निष्क्रिय किया जा चुका है। कश्मीर में शांति पाकिस्तान के लिए बिजली के झटके से कम नहीं है, क्योंकि वह लगातार घाटी में आतंकवादी हिंसा को बढ़ावा देकर उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थानीय आंदोलन के रूप में पेश करता रहा है। लेकिन मोदी सरकार की सतर्कता और लोगों के हितों से जुड़ी योजनाओं ने स्थानीय युवकों में आतंक के प्रति आकर्षण को लगभग खत्म सा कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। गृहमंत्री अब आतंकवाद के पूरे इको सिस्टम को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने न सिर्फ कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद पर लगाम लगाने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि इसके पहले वामपंथी उग्रवाद को भी समाप्त करने की उपलब्धि हासिल की है। मोदी सरकार के कार्यकाल में सुरक्षा बलों की जान पर आसन्न खतरे भी अब बहुत कम हो गए हैं। अब कोई भी आकड़े देख कर संतुष्ट हो सकता है कि 2016 के बाद आतंकवादी अब देश के भीतरी इलाकों में कोई बड़ा हमला करने में सफल नहीं हुए हैं। कारण साफ है कि अब पहले के मुकाबले हमारी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और किसी संभावित हमले से पहले ही नापाक तत्वों को पकड़ ले रही हैं। सक्रिय आतंकी समूहों के अधिकतर गुर्गे या तो मारे गए हैं या गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी पीओके से आसानी से घुसपैठ नहीं कर पाते। मोदी सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों पर प्रहार किए उसे पाकिस्तान में बैठे उनके आका वर्षों याद रखेंगे। मोदी सरकार ने आतंकवाद पर पूरी तरह नकेल डालने के लिए पिछले 12 सालों में बड़े पैमाने पर कानूनी बदलाव किए हैं। खासकर गृहमंत्री का एक ही मकसद रहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो-टॉलरेंस रखेंगे और उसी अप्रोच से काम करेंगे। मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल सुधार और इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन का काम पूरे शिद्दत से किया गया। सेंट्रल और स्टेट एजेंसियों के बीच इंटर-एजेंसी को-ऑर्डिनेशन पर सबसे अधिक जोर दिया गया। क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के साथ साथ 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी गई। टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए अलग से नेटवर्क बनाए गए, जिसमें विदेशी एजेंसियों के साथ तालमेल कर सोर्स पर प्रहार किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को आतंकी फंडिंग रोकने की विशेष जिम्मेदारी दी गई। सनद रहे कि 'राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 मुंबई हमले के बाद लागू किया गया। तभी से एनआईए भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के प्रति खतरा बन रहे संगठित अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है। पहले इसकी जांच का दायरा बहुत सीमित रखा गया, लेकिन 2019 में गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे दोनों सदनों की मंजूरी भी मिली। उसके बाद एनआईए के दायरे में कई तरह के नए अपराधों की जांच को शामिल कर दिया गया।

एक नजर

रामनगर को जाम मुक्त बनाने की मांग, लोक जागरण मंच ने प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनाती की उठाई आवाज

पश्चिम चंपारण,सद्भावना टुडे। रामनगर में लगातार बढ़ती यातायात जाम की समस्या को लेकर लोक जागरण मंच ने पुलिस प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मंच के पश्चिम चंपारण महामंत्री सैयद सईद सिद्दीकी ने पुलिस अधीक्षक, बगहा को पत्र लिखकर शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर नियमित ट्रैफिक पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में अंबेडकर चौक, सुंदर चौक, भगत सिंह चौक, भुवनेश्वर चौक और नहर रोड, सबुनी को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। मंच ने इन स्थानों पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में ट्रैफिक पुलिस की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और आम नागरिकों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके। इस संबंध में भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि रामनगर के डीएसपी और थानाध्यक्ष को भी प्रेषित की गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके। लोक जागरण मंच ने उम्मीद जताई है कि पुलिस प्रशासन जनहित और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस समस्या पर गंभीरता से विचार करेगा और जल्द आवश्यक कदम उठाएगा। मंच का कहना है कि प्रमुख चौराहों पर प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन से न केवल जाम की समस्या कम होगी, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी और स्थानीय लोगों, व्यापारियों तथा राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

बिहार के बेतिया के नौतन अंचल में बदहाली की दर्दनाक तस्वीर !



नौतन,सद्भावना टुडे। बाढ़ और सरकारी उपेक्षा के बीच नौतन अंचल के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं और अनेक समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं। कहीं बाढ़ का कहर, तो कहीं प्रशासनिक उदासीनता ने ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आखिर किन हालातों में जी रहे हैं गांव के लोग? उनकी समस्याएं क्या हैं और सरकारी दावों की जमीनी हकीकत क्या है? सद्भावना टुडे की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों की पीड़ा को सामने लाने की कोशिश की।

मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने की घोषणा का मुकुंद चौधरी ने किया स्वागत

दरभंगा। विद्यापति सेवा संस्थान के मिथिला विभूति पर्व समारोह के समापन अवसर पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी द्वारा मिथिला की भाषा, संस्कृति एवं शिक्षा के विकास को लेकर की गई घोषणाओं का जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी ने स्वागत किया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने की घोषणा ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में मैथिली शिक्षकों की नियुक्ति, मैथिली पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन तथा दरभंगा में नर्सरी से शोध स्तर तक संस्कृत की पढ़ाई के लिए गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेगी। वहीं, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की पहल भी सराहनीय है। मुकुंद चौधरी ने कहा कि मैथिली मिथिला की सभ्यता, संस्कृति और आत्मसम्मान की पहचान है, जबकि संस्कृत प्राचीन ज्ञान परंपरा की आधारशिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इन घोषणाओं को शीघ्र धरातल पर उतारकर मिथिला के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास को नई गति देगी। साथ ही उन्होंने सफल आयोजन के लिए विद्यापति सेवा संस्थान को साधुवाद दिया।

एलएनएमयू की सीनेट बैठक 19 दिसंबर को, दीक्षांत समारोह का बजट स्वीकृत

दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को सिंडिकेट की बैठक कुलपति के आवासीय कार्यालय स्थित सभागार में हाइब्रिड मोड में आयोजित हुई। बैठक में विश्वविद्यालय की वार्षिक अधिषद् (सीनेट) की बैठक 19 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। कुलसचिव डॉ. दिव्या रानी हंसदा ने बैठक का संचालन किया। राज्यपाल के अपर सचिव के पत्र के आलोक में सीनेट की बैठक की तिथि निर्धारित की गई। बैठक में सीनेट के आयोजन के लिए तैयार अनुमानित बजट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसे अनुमोदन के लिए बिहार लोक भवन, पटना भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं, आगामी 22 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अनुमानित बजट को भी सिंडिकेट ने स्वीकृति प्रदान की। इसे भी अनुमोदन के लिए बिहार लोक भवन भेजा जाएगा। बैठक में डॉ. बैद्यनाथ चौधरी 'बैजू', मीणा झा, डॉ. गजेन्द्र प्रसाद, प्रो. दिलीप कुमार चौधरी, प्रो. नारायण झा, प्रो. विमल कुमार, डॉ. शिखर वासिनी एवं डॉ. अमर कुमार सहित अन्य सिंडिकेट सदस्य उपस्थित थे। अंत में कुलसचिव डॉ. दिव्या रानी हंसदा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

सोनपुर मेला में कल कला-संस्कृति व श्रम विभाग के सौजन्य से होंगे रंगारंग कार्यक्रम

सारण। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के मनोरंजन तथा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 26 नवंबर को मेला परिसर स्थित मुख्य सांस्कृतिक मंच पर कला एवं संस्कृति विभाग तथा श्रम विभाग के संयुक्त सहयोग से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक श्रम विभाग के सहयोग से स्थानीय व चयनित कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके पश्चात संध्याकालीन सत्र में शाम 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कला एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से विशेष प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसमें गायिका नंदिनी मिश्रा अपने गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी, वहीं सी.पी.एस. स्कूल के छात्र-छात्राएं आकर्षक लोकनृत्य की छटा बिखेरेंगे। जिला प्रशासन का उद्देश्य इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करना और बिहार की लोककला को व्यापक पहचान दिलाना है।

कैबिनेट : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल में 11.884 डिसमिल बिहार सरकार की भूमि पर एसएसबी की 19वीं एवं 41वीं वाहिनी के वॉच टावर निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति सहित कुल 34 एजेंडों पर मपहर लगाई गई। इसके अलावे नालंदा के इस्लामपुर में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मौजा-ब्रहगांवा में 564.37 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 382.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत पटना जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,794.32 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे शहर में स्वच्छ एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

ग्राम कचहरियों को और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी के प्रशासनिक व्यय की वार्षिक राशि 4,000 से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2027 से 24,000 करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्राम कचहरियों के सुचारु संचालन और स्थानीय न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। समस्तीपुर में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए खानपुर अंचल के तीन मौजों में कुल 480 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 261.92 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही शेखपुरा में भी औद्योगिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करते हुए चेवाड़ा अंचल के तीन मौजों में कुल 250 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 62.37 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय



स्वीकृति प्रदान की गई है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) पटना में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के लिए 64 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के 17 नए पदों को भी स्वीकृति मिली है। साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियों के लिए 'बिहार मेडिकल फिजिसिस्ट सह रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सेवा संवर्ग नियमावली 2026' और 'बिहार प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक्स गैर-शैक्षणिक संवर्ग नियमावली 2026' के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाने और उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए 'बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद' के गठन को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र प्रायोजित 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना' को 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक विस्तार देते हुए इसके लिए 164 करोड़ 51 लाख 60 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही 'बिहार खनिज नियमावली 2026' को भी स्वीकृति मिली है।

पांच दिवसीय उमंग उत्सव का भव्य समापन, क्रिकेट फाइनल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

सुपौल। सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित पांच दिवसीय कॉलेज स्तरीय उत्सव 'उमंग 2026' का बुधवार को उत्साह और उल्लास के बीच भव्य समापन हुआ। 21 नवंबर से शुरू हुए इस उत्सव के अंतिम दिन खेल प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबले और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्रिकेट का फाइनल मुकाबला और विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां समारोह के मुख्य आकर्षण रहे। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ खेल, संस्कृति, साहित्य और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। अंतिम दिन क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज के कल्चरल क्लब के विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। उत्सव के पांच दिनों के दौरान क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शतरंज, कबड्डी और एथलेटिक्स सहित कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा निबंध लेखन, वाद-विवाद, क्विज, ग्रुप डिस्कशन, पोस्टर पेंटिंग और गायन जैसी प्रतियोगिताओं में भी विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा के साथ रचनात्मक और बौद्धिक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उल्लेखनीय है कि उमंग 2026 का शुभारंभ 21 नवंबर को कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एएन मिश्रा ने रिबन काटकर किया था। पांच दिनों तक चले इस आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आगे प्रमंडल स्तरीय उमंग प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आयोजन को यादगार बनाने में कॉलेज के मीडिया सेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मीडिया सेल की टीम ने उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियों को रिकॉर्ड कर उनका संकलन किया। इसमें समन्वयक सौरभ वर्मा, आनंद कुमार, अभिषेक कुमार, अमित कुमार, आनंद कुमार, अभिलाषा कुमारी, साक्षी कुमारी एवं तनिष्क कुमार ने योगदान दिया। फैकल्टी एडवाइजर पंकज सर के मार्गदर्शन में मीडिया सेल ने पूरे आयोजन की यादगार झलकियों को संकलित किया।

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी : गौतम कुमार

भागलपुर। बिहार जनसंघर्ष समिति की ओर से संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को 'संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर बढ़ता हमला' विषय पर एक विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष गौतम कुमार ने की, जबकि संचालन सुभाष कुमार प्रसाद ने किया। विमर्श को संबोधित करते हुए अध्यक्ष गौतम कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को सचेत और जागरूक होना होगा।

उन्होंने 26 नवंबर 1949 के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत इस दस्तावेज ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के सूत्र में पिरोया। वक्ता उज्ज्वल घोष और मो. बेलाल अंसारी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि सदियों से जातिगत उत्पीड़न, छुआछूत और आर्थिक असमानता झेल रहे वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के



सम्मानजनक जीवन की गारंटी है। मो. बाकिर हुसैन ने जातिवार जनगणना को लेकर चिंता जताई। उन्होंने जनगणना में एससी-एसटी की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग श्रेणी और जाति कोड की व्यवस्था न होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सटीक आंकड़ों के बिना सामाजिक न्याय की नीतियां बनाना कठिन है। वहीं, मंजर आलम ने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ चुनाव कराना नहीं, बल्कि संस्थाओं की स्वतंत्रता और सत्ता की जवाबदेही तय करना भी है। विमर्श के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 6 दिसंबर को डॉ. अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस और बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मो. अब्दुल फरीद, मो. जहांगीर आलम, मो. एहतेशाम आलम और मिनसार सहित कई लोग मौजूद थे।

सिल्ट कहीं समस्या तो कहीं उपयोगी भी, तकनीक अध्ययन के साथ होगा काम : विजय चौधरी

पटना। सिंचाई भवन स्थित विभागीय सभागार में उप मुख्यमंत्री-सह-जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार की नदियों के तल में गाद के जमाव एवं बालू के टीलों के निर्माण से नदियों के प्रवाह की दिशा एवं प्रकृति प्रभावित होती है। इससे तटबंधों, नदी तटों के संवेदनशील स्थलों एवं संबंधित संरचनाओं पर कटाव का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि सिल्ट कहीं समस्या है, तो कहीं उपयोगी भी है। इस चुनौती के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 बनाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदी से कहां और कितनी मात्रा में सिल्ट हटाई जानी है, इसका निर्धारण जल संसाधन विभाग तकनीकी अध्ययन के आधार पर करेगा। उन्होंने उपस्थित एजेंसियों के इस दिशा में प्रभावी एवं व्यावहारिक तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने की अपेक्षा की तथा आश्वस्त किया कि ऐसे प्रयासों में विभाग की ओर से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि आगामी बाढ़ प्रबंधन कार्ययोजना में ड्रेजिंग एवं सिल्ट रिमूवल को व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाएगा। इसके लिए सर्वेक्षण एवं तकनीकी अध्ययन के माध्यम से ऐसे स्थलों को चिह्नित किया जाएगा, जहां नदी की जल प्रवाह क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सिल्ट हटाने की आवश्यकता है। साथ ही, निकाली गई



सिल्ट के सुरक्षित परिवहन एवं निर्धारित स्थलों पर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नदी में ड्रेजिंग के दौरान निकाली गई गाद के परिवहन तथा विभिन्न कार्यस्थलों तक आवश्यक उपकरणों और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति में बार्ज का उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। सचिव ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य ड्रेजिंग एवं सिल्ट रिमूवल सहित बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए सक्षम एवं विशेषज्ञ एजेंसियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करना है, ताकि बाढ़ अवधि से पूर्व और बाढ़ के दौरान आवश्यकता के अनुरूप उनकी सेवाएं ली जा सकें। इस क्रम में ड्रेजिंग एवं सिल्ट रिमूवल के लिए आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की उपलब्धता, उनके संचालन एवं रखरखाव तथा आपात स्थिति में त्वरित कार्य निष्पादन की क्षमता को प्रमुख आधार बनाया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा में शामिल होगी मैथिली भाषा, एक सप्ताह में जारी होगी अधिसूचना : शिक्षा मंत्री



दरभंगा। डॉ. नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के तीसरे दिन मंगलवार की शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पर्यावरण मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. लक्ष्मीनिवास पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा में मैथिली भाषा को शामिल करने संबंधी अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। मैथिली में पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन होगा तथा विद्यालयों में मैथिली शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही दरभंगा में गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी, जहां नर्सरी से शोध स्तर तक संस्कृत की पढ़ाई की व्यवस्था होगी।

उन्होंने मिथिला की भाषा, संस्कृति और परंपरा को देश की अमूल्य धरोहर बताया। पर्यावरण मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने अशोक पेपर मिल के संबंध में भी जल्द निर्णय लेने की बात कही। वहीं, राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि महाकवि विद्यापति मिथिला की गौरवशाली पहचान हैं। उनकी स्मृति में 54 वर्षों से समारोह का आयोजन किया जाना सराहनीय सांस्कृतिक पहल है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता शंभुनाथ झा, प्रो. दिनेश झा, केशव कुमार चौधरी, डॉ. संजीव कुमार चौधरी एवं लोक गायिका जूली झा को मिथिला विभूति सम्मान प्रदान किया गया। अतिथियों का स्वागत विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉ. बैद्यनाथ चौधरी 'बैजू' ने किया। कार्यक्रम का संचालन पं. कमलाकांत झा ने किया।

नालसा की 'डॉन' व 'आशा' योजना पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम : युवाओं से सूखे नशे व बाल विवाह के खिलाफ आगे आने का आह्वान

कटिहार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रणवीर सिंह के मार्गदर्शन में बुधवार को दर्शन साह महाविद्यालय में नालसा की 'डॉन' एवं 'आशा' योजना के तहत एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. प्रशांत कुमार द्वारा मुख्य अतिथि न्यायाधीश सह सचिव कमलेश सिंह देऊ व अन्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र भेंट कर तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मंच संचालन तटवासी समाज न्यास के कवच परियोजना के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रोशन कुमार ने किया। संबोधन के दौरान न्यायाधीश सह सचिव कमलेश सिंह देऊ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानून की जानकारी पहुंचाना जिला विधिक सेवा प्राधिकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने 'जागृति', 'डॉन' और 'आशा' योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद सूखे नशे का बढ़ता दायरा गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आकर स्वयं नशे से दूर रहें और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। इस दौरान उन्होंने समानता के अधिकार, दहेज प्रतिषेध, महिला संरक्षण कानून तथा आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से बताया। प्रधानाचार्य डॉ. प्रशांत कुमार ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध इस पहल के लिए प्राधिकार का आभार जताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया। मुख्य न्याय रक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने प्राधिकार की निशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी दी, जबकि महिला विकास निगम वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक प्रभा पांडे ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 सहित महिला हेल्पलाइन (181), आपातकालीन सेवा (112), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और नालसा के टोल-फ्री नंबर (15100) के उपयोग पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रियंका कुमारी, कुमारी पायल, शिवी कुमारी, रोशनी सना, कोनिका कुमारी, अमर कुमार गुप्ता, रणविजय राय, चंद्रभान, आयुष कुमार और स्नेहा आंचल ने नारी सशक्तिकरण, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह रोकथाम और संविधान पर अपने विचार रखे। अंत में डॉ. शीला कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर डॉ. विवेकानंद स्वामी, प्राधिकार के सिंटू कुमार, मो. शाहनवाज, पीएलवी पवन कुमार, अमृता यूनिवर्सिटी के फरहान फारुकी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

एक नजर

बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स : 100 मीटर दौड़ में भारत और श्रीलंका ने जीते स्वर्ण पदक



भुवनेश्वर। बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत और श्रीलंका के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में भारत की मृत्तिका टी. और पुरुष वर्ग में श्रीलंका के दिनिथ इंदुवारा वीरारत्न ने स्वर्ण पदक जीते। पहले दिन कुल छह स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ, जिनमें से चार भारत और दो श्रीलंका के खिलाड़ियों के खाते में गए। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में मृत्तिका ने 12.02 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। श्रीलंका की के. रिसांसा हिरुपमा 12.07 सेकंड के साथ दूसरे और बांग्लादेश की देवान सुमाया 12.24 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में श्रीलंका के वीरारत्न ने 10.35 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के ऋषिप्रसाद देसाई ने 10.46 सेकंड में दौड़ पूरी कर रजत पदक जीता, जबकि श्रीलंका के साद जमालदीन 10.57 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। भारत के नील समराज 10.67 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे। भारत के अन्य स्वर्ण पदक पुरुष शॉटपुट, ट्रिपल जंप और 1500 मीटर दौड़ में आए। अनुराग सिंह कलेर ने 18.34 मीटर गोला फेंककर शॉटपुट का स्वर्ण जीता। दक्ष बिश्नोई ने 15.58 मीटर की छलांग के साथ ट्रिपल जंप में पहला स्थान हासिल किया, जबकि हितेश ने 3 मिनट 56.72 सेकंड में 1500 मीटर दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। महिला डिस्कस थ्रो में भारत ने दोहरा प्रदर्शन किया। प्रिया ने 52.03 मीटर के साथ स्वर्ण और निकिता कुमारी ने 50.02 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया।

राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के दिग्विजय सिंह ने ट्रैप स्पर्धा में जीता स्वर्ण



नई दिल्ली। डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में बुधवार को ट्रैप निशानेबाजी की विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड के दिग्विजय सिंह चौहान ने नेशनल सीनियर मास्टर पुरुष व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया। दिग्विजय ने फाइनल में 24 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। गुजरात के रोहित पांचाल 23 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें रजत पदक मिला। उत्तर प्रदेश के इकबाल नबी ने 19 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। दिग्विजय ने क्वालीफिकेशन राउंड में 90 अंकों के साथ छठा स्थान हासिल कर फाइनल में जगह बनाई थी। पंजाब के मनशेर सिंह 109 अंकों के साथ क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहे, लेकिन फाइनल में छठे स्थान पर खिसक गए। महिला मास्टर व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में गुजरात की बीना आनंद पटेल ने 88 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड की रितु सिंह 86 अंकों के साथ दूसरे और गुजरात की भारती सिंह 82 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। ट्रैप सीटेड स्पर्धा में राजस्थान के सुशील कुमार मीणा ने 68 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के दीपक सैनी 67 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में केवल दो निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। ट्रैप स्टैंडिंग (लोअर लिम्ब) पुरुष वर्ग में बिहार के अमरजीत गुप्ता ने 92 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। पंजाब के राजवीर सिंह सेखों 91 अंकों के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश के नदीम हुसैन 79 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला ट्रैप स्टैंडिंग (लोअर लिम्ब) वर्ग में उत्तर प्रदेश की वर्षा चौधरी एकमात्र प्रतिभागी रहीं। उन्होंने 84 अंक हासिल कर स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया।

सचिवालय प्रीमियर लीग में रॉयल रेंजर्स और डेंजर्स ने दर्ज की जीत

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित सचिवालय प्रीमियर लीग-2026 में सचिवालय रॉयल रेंजर्स और सचिवालय डेंजर्स ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। पहले मुकाबले में रॉयल रेंजर्स ने सचिवालय यूनाइटेड को छह विकेट से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में सचिवालय डेंजर्स ने सचिवालय स्मैशर्स को शिकस्त दी। पहले मुकाबले में टॉस के बाद बल्लेबाजी करने उतरी सचिवालय यूनाइटेड की टीम ने निर्धारित ओवरों में छह विकेट खोकर 172 रन बनाए। टीम की ओर से सचिन बिष्ट ने 46, संतोष पांडे ने 29 और अरविंद दानू ने 20 रन का योगदान दिया। रॉयल रेंजर्स की ओर से अजीत शर्मा और हितेश छेत्री ने दो-दो विकेट हासिल किए। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल रेंजर्स की टीम ने 15.5 ओवर में चार विकेट खोकर 174 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम के ऑलराउंडर अजीत शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए, जबकि कप्तान टिकराज ने 26 रन का योगदान दिया। यूनाइटेड की ओर से अंकित नौटियाल, सिद्धार्थ उनियाल और संतोष पांडे ने एक-एक विकेट लिया। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए अजीत शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में सचिवालय डेंजर्स ने सचिवालय स्मैशर्स को हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्मैशर्स की टीम 13 ओवर में 68 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से अशोक ने सर्वाधिक 16 रन बनाए। डेंजर्स की ओर से शीशपाल रावत ने चार और रविंदर ने तीन विकेट लिए। 69 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिवालय डेंजर्स की टीम ने सात विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। टीम की ओर से मनोज भट्ट ने 34 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। स्मैशर्स की ओर से नूर मोहम्मद ने तीन विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी के लिए शीशपाल रावत को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

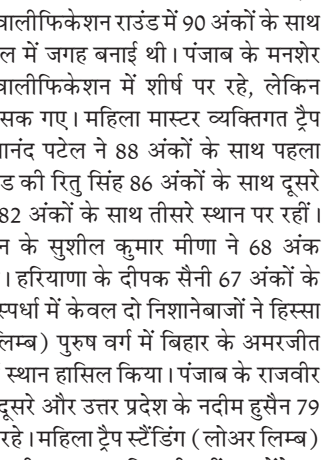

भारतीय महिला हॉकी टीम 24 घंटे में पांचवें से चौथे स्थान पर पहुंची, विश्व रैंकिंग में बनाया नया इतिहास

भोपाल,एजेंसी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महज 24 घंटे के भीतर अपनी ही उपलब्धि को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 में जापान को 4-0 से हराने के बाद भारतीय टीम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की ताजा विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले ही चीन को 6-2 से हराकर टीम पहली बार विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान पर पहुंची थी। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में मिली जापान के खिलाफ जीत ने भारतीय टीम को अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्थिति दिलाई। एशिया की दो मजबूत टीमों चीन और जापान के खिलाफ लगातार मिली जीत से भारत की रैंकिंग में यह बड़ी छलांग लगी है। जापान पर 4-0 की जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और लीग चरण में अपना अजेय अभियान पूरा करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।

चीन के खिलाफ भारत की 6-2 की जीत भी खास रही थी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में चीन के खिलाफ भारत की यह सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले भारतीय टीम ने 2013 के संस्करण में चीन को 4-2 से हराया था। इसके बाद जापान के खिलाफ मिली जीत ने टीम के बढ़ते आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता को और मजबूत किया। भारत ने टूर्नामेंट में मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान को हराया है। कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में गत चैंपियन भारतीय टीम अब महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का



रिकॉर्ड चौथा खिताब जीतने और लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचना भारतीय महिला हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अक्टूबर 2003 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग शुरू होने के बाद भारतीय टीम की पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग नौवीं थी, जो 2018 में विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद हासिल हुई थी। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल करने के बाद टीम आठवें नंबर पर पहुंची थी। इसके बाद 2022 में एफआईएच प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर मई-जून में छठा स्थान हासिल किया था। भारतीय टीम 2023 में भी छठे स्थान पर पहुंची थी। भारतीय हॉकी के लिए 2026 का साल शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। टीम ने एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीता, एफआईएच हॉकी विश्व कप में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल किया, जो 1974 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके अलावा 44 साल के अंतराल के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। अब विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचना इस यादगार वर्ष की एक और बड़ी उपलब्धि बन गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी में भारत की मजबूत स्थिति भी स्थापित हुई है। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने बधाई देते हुए कहा, 'विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचना भारतीय हॉकी के लिए गर्व का क्षण है। यह हमारे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

जहीर खान की नई पहल 'इक्वल' से क्रिकेट में आएगा बड़ा बदलाव, एक ही टीम में खेलेंगे महिला और पुरुष खिलाड़ी

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और 2011 विश्व कप विजेता जहीर खान को नई मिश्रित टी20 क्रिकेट लीग 'इक्वल' की अपार संभावनाओं पर पूरा भरोसा है। यह महत्वाकांक्षी पहल क्रिकेट के पारंपरिक प्रारूप को चुनौती देते हुए महिला और पुरुष खिलाड़ियों को एक ही एकादश में खेलने का अवसर देगी। इस पहल की परिकल्पना एंकर स्पोर्ट्स ने की है, जिसके सह-मालिक जहीर खान और सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमी नागेंद्र सिद्धौताम हैं। इसे जर्मन क्रिकेट महासंघ के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। पहली बार इस तरह की मिश्रित महिला-पुरुष क्रिकेट लीग शुरू करने की तैयारी है। 'इक्वल' में पेशेवर महिला और पुरुष क्रिकेटर एक साथ मैदान पर उतरेंगे। इससे टी20 प्रारूप को एक नया और समावेशी स्वरूप मिलेगा। पुरुष और महिला क्रिकेट के अलग-अलग टूर्नामेंटों की परंपरा से हटकर इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी एक ही लीग में हिस्सा लेंगे। इसमें एक ही अंकतालिका होगी और एक ही टीम चैंपियन बनेगी। प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार, पहले संस्करण में पांच टीमें कुल 12 टी20 मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ी होंगे। हर मैच की एकादश में छह महिला और पांच पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे। टी20 क्रिकेट के मौजूदा नियमों को बरकरार रखते हुए इस प्रारूप में खेलने के स्पष्ट नियम, खिलाड़ियों की सुरक्षा के उपाय और स्थानापन्न खिलाड़ियों से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे, ताकि प्रतियोगिता को व्यवस्थित और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

एंकर स्पोर्ट्स के सह-मालिक जहीर खान ने कहा, 'क्रिकेट में लोगों को एकजुट करने की ताकत है। खासकर यूरोप जैसे उभरते बाजारों में इस खेल का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे कितने व्यापक दर्शक वर्ग के लिए सुलभ बना पाते हैं। 'इक्वल' जैसी पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह सभी लिंगों के लोगों को खेल में हिस्सा लेने, योगदान देने और क्रिकेट के विकास का हिस्सा बनने का अवसर देती है। उन्होंने कहा, '2028 में क्रिकेट की ओलंपिक खेलों में वापसी के साथ इस खेल को नए समुदायों तक पहुंचाने और इसकी वैश्विक पहुंच बढ़ाने का अवसर है। 'इक्वल' को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें एक महिला और एक पुरुष क्रिकेटर एक साथ मैदान पर उतरेंगे और एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे।

हरिद्वार टी-20 लीग का प्लेयर ड्राफ्ट संपन्न, छह टीमों की जर्सी और ट्रॉफी का अनावरण

हरिद्वार। उत्तराखंड में स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में हरिद्वार टी-20 लीग की तैयारियां तेज हो गई हैं। लीग के आगामी सत्र के लिए 23 नवंबर को हरिद्वार स्थित हयात प्लेस में प्लेयर ड्राफ्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान टूर्नामेंट की ट्रॉफी और छह फ्रेंचाइजी की आधिकारिक जर्सियों का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम में सभी छह टीमों के प्रतिनिधि पहली बार एक साथ जुटे।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की स्वीकृति प्राप्त इस लीग का आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार कर रहा है, जबकि प्रबंधन की जिम्मेदारी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी 100 स्पोर्ट्स को सौंपी गई है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा और कोषाध्यक्ष मानस मिंगवाल सहित क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार के अध्यक्ष पविंदर सिंह तथा सचिव एवं लीग के चेयरमैन अमित कुमार रॉय मौजूद रहे। लीग का उद्देश्य हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक टी-20 क्रिकेट का मंच उपलब्ध कराना है। इसके लिए आयोजित ट्रायल में 600 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। प्लेयर ड्राफ्ट के दौरान छह फ्रेंचाइजी ने अपनी-अपनी टीमों का गठन किया। इनमें रुड़की स्ट्राइकर्स, गंगाज वॉरियर्स, वेदांता रॉयल्स, भगवानपुर हीरोज, हर की पौड़ी नाइट्स और ज्वाला किंग्स शामिल हैं। लीग के चेयरमैन अमित कुमार रॉय ने कहा कि हरिद्वार में क्रिकेट प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए अब तक पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए थे। इस लीग के माध्यम से उन्हें अपने ही क्षेत्र में बेहतर मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि ट्रायल में 600 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी से इस तरह के आयोजन की जरूरत का पता चलता है। प्लेयर ड्राफ्ट का सफल आयोजन लीग की तैयारियों में महत्वपूर्ण पड़ाव है। ट्रॉफी और जर्सियों के अनावरण के साथ सभी टीमों को आगामी प्रतियोगिता के लिए अलग पहचान मिली। लीग के सभी मुकाबले हरिद्वार के एचआरडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। आयोजकों के अनुसार, इस प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, टीम का प्रतिनिधित्व करने और संगठित टी-20 क्रिकेट के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल का अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, पंत छठे, गिल सातवें और जायसवाल नौवें स्थान पर पहुंचे

दुबई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन का असर आईसीसी की ताजा टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में देखने को मिला है। वेलिंगटन में खेला गया यह मुकाबला ड्रॉ रहा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी बेहतरीन पारियों के दम पर रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। ऋषभ पंत, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अब शीर्ष 10 में शामिल हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों में ऋषभ पंत सबसे आगे बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 128 रन की आकर्षक पारी खेलने वाले पंत एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 98 रन की पारी के दम पर तीन स्थान की छलांग लगाई और सातवें स्थान पर पहुंच गए। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 85 रन बनाने के बाद पांच स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर आ गए हैं। इस तरह अब तीन भारतीय बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं।

वेलिंगटन में भारत की पहली पारी में नौ विकेट पर 720 रन बनाकर घोषित किए गए स्कोर में सर्वाधिक 136 रन बनाने वाले केएल राहुल को भी फायदा हुआ है। वह चार स्थान ऊपर चढ़कर 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं। देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें 15 स्थान का फायदा हुआ और वह 39वें नंबर पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में प्लेयर ऑफ द मैच हेनरी निकोल्स को सबसे अधिक फायदा हुआ है। उन्होंने नाबाद 175 और 31 रन की पारियां खेलीं, जिसके दम पर वह 10 स्थान



ऊपर चढ़कर 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ग्लेन फिलिप्स ने 118 और नाबाद 26 रन बनाए थे। उन्हें 13 स्थान का फायदा हुआ और वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 17वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट तथा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के बाद जारी ताजा रैंकिंग में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को भी फायदा हुआ है। पहली पारी में 137 रन बनाने वाले तौहीद हृदोय 28 स्थान ऊपर चढ़कर 33वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लिटन दास ने 120 रन की पारी खेली थी, जिसके बाद वह नौ स्थान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन करियर की सर्वश्रेष्ठ संयुक्त 15वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि मार्क्स एकरमैन 60वें स्थान पर हैं।

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेलिंगटन टेस्ट में पांच विकेट लिए थे। इसके दम पर वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को भी फायदा हुआ है। जोहान्सबर्ग टेस्ट में आठ विकेट लेकर अपनी टीम को नौ विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले रबाडा दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने भी दो स्थान की छलांग लगाई है। रावलपिंडी टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए अब्बास ने दोनों पारियों में तीन-तीन विकेट लिए थे। वह अब 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी की पुरुष वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बेन डकेट को तीन स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में निर्णायक तीसरे वनडे में 115 गेंदों पर 133 रन की अहम पारी खेलने वाले डकेट करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। उनके सलामी जोड़ीदार टॉम बेंटन भी करियर की सर्वश्रेष्ठ 12वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में गस एटकिंसन 10 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें, लियाम डॉसन 14 स्थान की छलांग लगाकर 39वें और नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने सात स्थान ऊपर चढ़कर 34वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आईसीसी की पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में इंग्लैंड के फिल साल्ट दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कैरारा में 30 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली थी। टॉम बेंटन ने दो पारियों में 39 और नाबाद 26 रन बनाए, जिसके बाद वह 26 स्थान ऊपर चढ़कर 34वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

टाटा आईपीएल-2027 की नीलामी के लिए 1220 खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण, 66 स्थानों के लिए लगेगी बोली

नई दिल्ली। टाटा आईपीएल-2027 की खिलाड़ी नीलामी के लिए कुल 1220 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें 939 भारतीय और 17 देशों के 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने 184 खिलाड़ियों को अपने साथ बरकरार रखा है या चुना है। ऐसे में नीलामी के दौरान अधिकतम 66 स्थान भरे जाने हैं, जिनमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के स्थान शामिल हैं। पंजीकृत खिलाड़ियों में 184 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी, 994 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है और 42 खिलाड़ी एसोसिएट देशों से हैं। बिना अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ियों में 925 भारतीय हैं। इनमें से 127 खिलाड़ी पहले भी आईपीएल के किसी सत्र में खेल चुके हैं।

विदेशी खिलाड़ियों के पंजीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। वहां के 53 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के 40, वेस्टइंडीज के 36, न्यूजीलैंड के 25 और अफगानिस्तान के 23 खिलाड़ी सूची में शामिल हैं। एसोसिएट देशों में अमेरिका के 13 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के 10-10 खिलाड़ी नीलामी की दौड़ में हैं।

छह श्रेणियों में बांटे गए खिलाड़ी

नीलामी के लिए पंजीकृत 1220 खिलाड़ियों को छह श्रेणियों में रखा गया है। इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके 14 भारतीय खिलाड़ी और 170 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। एसोसिएट देशों के 42 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा, पहले आईपीएल खेल चुके 127 गैर-अंतरराष्ट्रीय भारतीय खिलाड़ी, 798 अन्य गैर-अंतरराष्ट्रीय भारतीय खिलाड़ी और 69 गैर-अंतरराष्ट्रीय विदेशी खिलाड़ी सूची में शामिल हैं।

देश के अनुसार खिलाड़ियों का पंजीकरण

देश के अनुसार देखें, तो भारत के 939 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। ऑस्ट्रेलिया के 53, दक्षिण अफ्रीका के 40, वेस्टइंडीज के 36, न्यूजीलैंड के 25, अफगानिस्तान के 23 और श्रीलंका के 21 खिलाड़ी सूची में हैं। इंग्लैंड के 16, अमेरिका के 13, बांग्लादेश के 12, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के 10-10 तथा आयरलैंड के सात खिलाड़ी शामिल हैं। जिम्बाब्वे के छह, नीदरलैंड के तीन, जबकि कनाडा, जापान और स्कॉटलैंड के दो-दो खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। अब फ्रेंचाइजी नीलामी के लिए पंजीकृत सूची में से उन खिलाड़ियों के नाम सौंपेंगी, जिन्हें वे अंतिम खिलाड़ी सूची में शामिल करने के लिए विचारार्थ रखना चाहती हैं। अंतिम नीलामी सूची और खिलाड़ियों के समूह चार दिसंबर 2026, शुक्रवार को जारी किए जाएंगे।

फ्रेंचाइजी के पास 295.60 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध



नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी के पास कुल 66 स्थान खाली हैं। इनमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के स्थान हैं। टीमों ने अब तक कुल 1004.40 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उनके पास वेतन सीमा के तहत कुल 295.60 करोड़ रुपये शेष हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पास 19 खिलाड़ी हैं, जिनमें छह विदेशी हैं। टीम ने 101.95 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 28.05 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे छह खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास 16 खिलाड़ी हैं, जिनमें चार विदेशी हैं। टीम ने 90.50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 39.50 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे नौ खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें चार विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

गुजरात टाइटंस के पास 22 खिलाड़ी हैं, जिनमें छह विदेशी हैं। टीम ने 121.25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 8.75 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे तीन खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 17 खिलाड़ी हैं, जिनमें पांच विदेशी हैं। टीम ने 88.35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 41.65 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे आठ खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें तीन विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 18 खिलाड़ी हैं, जिनमें पांच विदेशी हैं। टीम ने 82.55 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 47.45 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे सात खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें तीन विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

मुंबई इंडियंस के पास 16 खिलाड़ी हैं, जिनमें छह विदेशी हैं। टीम ने 99.75 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 30.25 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे नौ खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। पंजाब किंग्स के पास 19 खिलाड़ी हैं, जिनमें छह विदेशी हैं। टीम ने 111.40 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 18.60 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे छह खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 20 खिलाड़ी हैं, जिनमें सात विदेशी हैं। टीम ने 115.85 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 14.15 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे पांच खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें एक विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स के पास 19 खिलाड़ी हैं, जिनमें पांच विदेशी हैं। टीम ने 102.95 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 27.05 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे छह खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें तीन विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के पास 18 खिलाड़ी हैं, जिनमें पांच विदेशी हैं। टीम ने 89.85 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उसके पास 40.15 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे सात खिलाड़ियों की जगह भरनी है, जिनमें तीन विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

एक नजर

प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2026 का ताज



सैन जुआन,एजेंसी। प्यूर्टो रिको की 27 वर्षीय जेनिफर बैरेटो ने मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। सैन जुआन में आयोजित प्रतियोगिता के 75वें संस्करण में 116 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जेनिफर ने अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन से सभी को पीछे छोड़ दिया। उन्हें वर्ष 2025 की मिस यूनिवर्स विजेता मेक्सिको की फातिमा बॉश ने ताज पहनाया। इस बार प्रतियोगिता का आयोजन प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित जोस मिगुएल एग्रेलोट कोलिजियम में किया गया। कई हफ्तों तक चली इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों की संस्कृति और प्रतिभा की झलक देखने को मिली। इस साल प्रतियोगिता के 75वें संस्करण के मौके पर एक खास ताज भी पेश किया गया। 'द रेडियंस ऑफ एन इटरनल लेगेसी' नाम के इस ताज को ज्वेलरी डिजाइनर जॉर्ज विटल्स ने पेरिस के ज्वेलरी हाउस 'मेसन डी'ओर' के साथ मिलकर तैयार किया। 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बने इस ताज में 3,150 हीरे जड़े गए हैं। हालांकि, इस बार की प्रतियोगिता केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि विवादों के कारण भी चर्चा में रही। वीजा संबंधी परेशानियों और फ्रेंचाइजी विवादों के चलते कुछ देशों की प्रतिभागियों को प्रतियोगिता से हटना पड़ा। वहीं, इजराइल की प्रतिभागी की नेशनल कॉस्ट्यूम को लेकर भी सोशल मीडिया पर विरोध देखने को मिला। भारत के केरल की 19 वर्षीय काजिया लिज मेजो ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने टॉप-30 में जगह बनाकर देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन स्विमसूट राउंड के बाद टॉप-12 में पहुंचने से चूक गईं। मॉडल होने के साथ कानून की छात्रा काजिया ने इसी साल मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली केरल की पहली महिला बनी थीं। इससे पहले 2024 में उन्होंने मिस टीन दिवा का खिताब जीता था और 2025 में मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फर्स्ट रनर-अप रही थीं।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आठ आतंकवादी मारे गए



इस्लामाबाद। देश के अशांत उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में आठ आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह अभियान पेशावर और बन्नू जिलों में चलाए गए। डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट ने सोमवार रात प्रांतीय राजधानी पेशावर के बाहरी इलाके बडबेर में हुई गोलीबारी में पांच आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों ओर से 25 मिनट गोलीबारी हुई। इस दौरान इन आतंकवादियों का सरगना तीराह घाटी निवासी कमांडर ताज मोहम्मद उर्फ शिनय भागने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को ऐसे ही अभियान में 'जरगुल उर्फ अंकल' समूह के तीन आतंकवादी मारे गए। यह अभियान घररेहा शाहजहां, किंगार और आसपास के गांवों में चलाया गया। इससे पहले सोमवार को प्रांतीय राजधानी से 23 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पसानी गांव में ऐसे ही अभियान में तीन आतंकवादी मारे गए। इनकी पहचान अब्दुल रशीद, सईदुल्लाह और सईद नवाब के रूप में हुई है। मारे गए आतंकवादियों के पास से दो कलाश्निकोव (राइफल), एक पिस्तौल, तीन हैंड ग्रेनेड, पांच मैगजीन और कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र बरामद किए गए। आतंकवादियों की मदद करने के संदेह में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, मारे गए लोगों में से एक 'ज़रगुल उर्फ अंकल' का भतीजा है। यह समूह प्रतिबंधित संगठन है। इन आतंकवादियों पर पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय शांति समितियों के प्रमुखों और आम नागरिकों पर हमले करने के साथ-साथ जबरन वसूली, लूटपाट और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप है।

यूक्रेन का रूस के प्रमुख सैन्य एयरबेस पर हमले का दावा, पांच विमान क्षतिग्रस्त

कीव। यूक्रेन ने बुधवार को रूस के एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डे पर लंबी दूरी तक मार करने वाले हमले का दावा किया है। इस हवाई हमले में पांच विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक निजनी नोवगोरोद क्षेत्र स्थित सवास्लेयका एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसमें तीन मिग-31 लड़ाकू विमान और दो एसयू-34 लड़ाकू-बमवर्षक विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन विमानों को कुछ समय के लिए परिचालन से बाहर करना पड़ा है। रूस की ओर से इस दावे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने बताया कि हमले का उद्देश्य रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। मिग-31 विमानों का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के लिए किया जाता है, जबकि एसयू-34 विमान लड़ाकू और बमबारी अभियानों में इस्तेमाल होते हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब यूक्रेनी सेना ने हाल के दिनों में रूस से जुड़े कई ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन के अनुसार, लीबिया के समुद्री क्षेत्र में दो रूसी जहाजों और फिनलैंड की खाड़ी में एक अन्य रूसी पोत पर भी हमले किए गए। पिछले सप्ताह क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से जोड़ने वाले प्रमुख पुल के सड़क हिस्से को भी लगातार हमलों के बाद नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टर्की पक्षियों को दिया जीवनदान, व्हाइट हाउस की सालाना परंपरा निभाई



वाशिंगटन,एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्सगिविंग त्योहार से पहले व्हाइट हाउस में आयोजित एक विशेष समारोह में दो टर्की पक्षियों को जीवनदान दिया। इन पक्षियों के नाम 'फ्रीडम' और 'फेदर्स' हैं। अमेरिका में हर साल थैंक्सगिविंग से पहले राष्ट्रपति की ओर से टर्की पक्षियों को माफी देने की परंपरा है। मंगलवार को आयोजित समारोह में ट्रंप ने दोनों पक्षियों का परिचय कराया और अमेरिकी नागरिकों को थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने यह शुभकामना अपने परिवार और अमेरिका की प्रथम महिला की ओर से भी दी। यह व्हाइट हाउस की छुट्टियों से जुड़ी सबसे चर्चित परंपराओं में से एक है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष व्हाइट हाउस में 79वां समारोह आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 1947 में हुई थी।

1947 में नेशनल टर्की फेडरेशन ने तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को टर्की पक्षी भेंट किए थे। हालांकि, इस पक्षी को औपचारिक रूप से माफी देने की परंपरा वर्ष 1989 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में शुरू हुई। इस साल समारोह के लिए चुने गए दोनों टर्की पक्षियों को वेस्ट वर्जीनिया के फोर्ट साइबर्ट में स्कॉट और बेकी राइटसेल ने अपने फार्म पर पाला। राइटसेल परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा है। परिवार के लिए व्हाइट हाउस में अपने फार्म के पक्षियों को प्रस्तुत करना बड़ी उपलब्धि है। व्हाइट हाउस में दोनों टर्की पक्षियों को माफी देने का कार्यक्रम व्हाइट हाउस के नए हेलीपैड पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि अगले साल टर्की को माफी देने का कार्यक्रम उनके नए बॉलरूम में होगा। बॉलरूम को उन्होंने अमेरिका में अब तक बनी सबसे मजबूत इमारत बताया। स्कॉट राइटसेल ने इस आयोजन को टर्की पालने वाले किसानों के लिए बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन किसानों के लिए किसी बड़े खेल मुकाबले यानी 'सुपर बाउल' जैसा है। नेशनल टर्की फेडरेशन की अध्यक्ष क्रिस्टी पफेनबार्गर के अनुसार, इन दोनों पक्षियों को समारोह के लिए तैयार करने का काम फरवरी में ही शुरू हो गया था। जुलाई में जब वे छोटे चूजों के रूप में फार्म पर पहुंचे, तब से उनकी खास देखभाल की गई। व्हाइट हाउस में समारोह के दौरान लोगों की भीड़, कैमरों की चमक और तेज आवाजों से पक्षी घबराएं नहीं, इसके लिए राइटसेल परिवार रोजाना उन्हें इन परिस्थितियों का अभ्यस्त बनाता था।

दोनों पक्षियों का चयन उनके स्वभाव और शारीरिक बनावट को देखकर किया गया। राइटसेल के अनुसार, इसके लिए पक्षियों का सुंदर दिखना और शांत स्वभाव का होना जरूरी था। उन्होंने इसकी तुलना सौंदर्य प्रतियोगिता से की। स्कॉट राइटसेल ने कहा कि जब उन्हें इस आयोजन के लिए चुना गया तो उनका पूरा परिवार बेहद खुश हुआ। उनके फार्म पर पाले गए पक्षियों को अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाना उनके लिए गर्व की बात है। थैंक्सगिविंग अमेरिका का प्रमुख त्योहार है। इस दिन परिवार और मित्र एक साथ भोजन करते हैं और जीवन में मिली खुशियों व अच्छी चीजों के लिए आभार जताते हैं। इस मौके पर टर्की का मांस परोसने की परंपरा भी काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रपति की ओर से दो टर्की पक्षियों को माफी देने का मतलब है कि उन्हें खाने के लिए नहीं मारा जाएगा और वे सुरक्षित रहेंगे। ट्रंप ने एक टर्की से कहा, 'फ्रीडम, इस पल से तुम्हें पूरी तरह से माफा दी जाती है।' राष्ट्रपति ने बताया कि दूसरा टर्की 'फेदर्स' झाड़ियों में भाग गया, लेकिन उसे भी माफी दी जाएगी। 'फ्रीडम' और 'फेदर्स' को सोमवार को वाशिंगटन के विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में प्रस्तुत किया गया। व्हाइट हाउस जाने से पहले ये दोनों वहीं एक सुइट में रुके हुए थे। व्हाइट हाउस से यह दोनों पक्षी टेक्सास के कॉलेज स्टेशन जाएंगे। वहां वे अपना बाकी जीवन बिताएंगे। 'फ्रीडम' और 'फेदर्स' को तो बख्श दिया गया है, लेकिन नेशनल टर्की फेडरेशन का अनुमान है कि इस थैंक्सगिविंग पर देश भर में लगभग 30 मिलियन टर्की लोगों की खाने की मेज तक पहुंचेंगी। राइटसेल परिवार के लिए मंगलवार का यह कार्यक्रम उन किसानों और मजदूरों को सम्मान देने का भी एक मौका है, जिनकी बदौलत इस थैंक्सगिविंग पर अमेरिकियों की थाली में भोजन पहुंच पाता है। राइटसेल ने कहा, 'शहरों में बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना बस जादू से वॉलमार्ट में आ जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है।'

नेपाल में बाढ़ के बाद लापता 213 भारतीयों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू, परिजनों से 2 दिसंबर तक मांगी आपत्ति



काठमांडू। नेपाल में 26 अगस्त को त्रिशूली-भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लापता हुए 213 भारतीय नागरिकों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेपाल सरकार ने लापता भारतीय नागरिकों की सूची में शामिल लोगों के परिजनों से विवरण में किसी भी तरह की त्रुटि, संशोधन या आपत्ति होने पर 2 दिसंबर तक जानकारी देने को कहा गया है।

काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार नेपाल के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 213 लापता भारतीय नागरिकों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। दूतावास ने कहा है कि यदि लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को सूची में शामिल नाम, व्यक्तिगत विवरण या अन्य जानकारियों को लेकर कोई आपत्ति है अथवा उसमें संशोधन या नाम जोड़ने एवं हटाने का अनुरोध करना है, तो वे 2 दिसंबर से पहले भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए दूतावास ने ईमेल द्गश्द्वद्मड्डह्लद्धद्वड्डठ्ठ-स्रह्वद्धद्यशश्स्रह्यह्वश्चश्चशह्लह्लञ्चद्दद्वड्डद्व द्य.ष्शद्व और मोबाइल नंबर +9779851316807 जारी किया है। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सऐप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। दूतावास के मुताबिक आपत्तियां और संशोधन संबंधी सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नेपाल सरकार अंतिम सूची तैयार कर लापता व्यक्तियों को औपचारिक रूप से मृत घोषित करेगी। इसके बाद भारतीय दूतावास नेपाल के स्थानीय प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस दौरान लापता व्यक्तियों के परिजनों से कुछ अतिरिक्त जानकारियां और आवश्यक दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। दूतावास ने कहा है कि इस संबंध में आगे की जानकारी आने वाले दिनों में उपलब्ध कराई जाएगी।

काठमांडू एयरपोर्ट पर 2.34 किलो संदिग्ध सोने के साथ दो चीनी महिलाएं गिरफ्तार, शरीर के अंदर छिपाकर लाई थीं



काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने जैसी दिखने वाली पीले रंग की अर्धठोस धातु के साथ दो चीनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। बरामद पदार्थ का कुल वजन 2 किलो 348 ग्राम बताया गया है। दोनों महिलाएं इसे अपने शरीर के मलद्वार और अंतर्वस्त्रों में छिपाकर हांगकांग से काठमांडू लाई थीं। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों महिलाओं को सीमा शुल्क क्षेत्र पार कर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका गया।

पुलिस के मुताबिक, दोनों महिलाएं मंगलवार देर रात 11:15 बजे कैथे पैसिफिक एयरलाइंस की उड़ान से हांगकांग से काठमांडू पहुंची थीं। उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की। तलाशी के दौरान उनके मलद्वार और अंतर्वस्त्रों के भीतर प्लास्टिक में लपेटकर छिपाए गए सोने जैसे दिखने वाले पीले रंग के अर्धठोस पदार्थ के आठ गोलाकार टुकड़े बरामद किए गए। प्लास्टिक रैप सहित इनका कुल वजन 2 किलो 348 ग्राम पाया गया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान चीन के गुआंगडोंग प्रांत की 45 वर्षीय लिन लिना और 35 वर्षीय लिन जिनपिंग के रूप में हुई है। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सुरक्षा कार्यालय के सह-प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक ढुण्डीराज न्यौपाने के अनुसार, दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर आवश्यक जांच की जा रही है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए मंगलवार को ही त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल सीमा शुल्क कार्यालय को सौंपने की जानकारी पुलिस ने दी है। बरामद पीले अर्धठोस पदार्थ की वास्तविक प्रकृति और उसमें सोने की मात्रा की आधिकारिक पुष्टि इस प्रेस विज्ञप्ति में नहीं की गई है।

बांग्लादेश में कपड़ा कर्मचारी न्यूनतम वेतनमान 30 हजार टका करने पर अड़े

आंदोलन तेज, दागे गए आंसू गैस के गोले



ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश सरकार को आखिरकार आंदोलनरत कपड़ा उद्योग (रेडीमेड गारमेंट) कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान को 12,500 टका से बढ़ाकर 17,000 टका करने की घोषणा करनी पड़ी। कर्मचारी इसे 30,000 टका करने की जिद पर अड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने इस घोषणा के बाद आंदोलन को और तेज कर दिया। इस बीच ढाका सहित आठ जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की कुल 108 प्लाटून तैनात की गई हैं। इनमें से 56 प्लाटून अकेले गोपालगंज में तैनात हैं। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर में स्वदेश लौटने की घोषणा के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है। हसीना की पार्टी अवामी लीग प्रदर्शन कर रही है।

प्रोथोम अलो, बीडी न्यूज 24 डॉट कॉम और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों के आंदोलन के कारण औद्योगिक शहरों में बिगड़ती स्थिति के बीच फैक्टरी मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। ढाका के सेगुनबगीचा स्थित मिनिमम वेज बोर्ड कार्यालय में 12 घंटे तक बैठक चली। यह बैठक मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू होकर बुधवार सुबह करीब 2 बजे खत्म हुई। बताया गया है कि फैक्टरी मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद छह सदस्यीय बोर्ड ने मतदान के जरिए नया न्यूनतम वेतन तय किया। बोर्ड के अनुसार न्यूनतम वेतनमान 12,500 टका को बढ़ाकर 17,000 टका कर दिया गया है। गाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह इस घोषणा पर नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों ने दो राजमार्गों पर कई जगहों पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ को राजमार्ग से हटाने की कोशिश की तो टकराव शुरू हो गया। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड दागने पड़े। गाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक मो. अमजद हुसैन ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे ढाका-मयमनसिंह और ढाका-तंगैल राजमार्ग पर भोगरा बाईपास, नाओजोर और सालना इलाकों सहित कई कारखानों के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चंदना चौराहे से भोगरा बाईपास, बोर्ड बाजार के साइनबोर्ड, नाओजोर, भवाल मिर्ज़ापुर और मास्टरबारी तक के इलाकों में मजदूरों ने सड़कों और राजमार्गों पर यातायात बाधित कर दिया। पुलिस और बीजीबी ने हटाने का प्रयास किया तो ईंट-पत्थर फेंके गए। जवानों ने आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड दागकर स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की। उधर, गाजीपुर सदर उपजिला के भवाल मिर्जापुर इलाके में स्थित क्वाट्रो फैशन, लैला गारमेंट्स, रागाडी फैशन, राजेंद्रपुर के बांग्लाबाजार और कई अन्य गारमेंट फैक्टरियों के कर्मचारियों ने काम पर लौटने के बजाय बांग्लाबाजार-भवाल मिर्जापुर और मास्टरबारी-भवाल मिर्जापुर क्षेत्रीय सड़कों और ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जाम में सैकड़ों वाहन चालक बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। इस बीच गाजीपुर के श्रीपुर में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने मार्च निकाला। बीएनपी ने औद्योगिक क्षेत्र में फैली अशांति और फैक्टरियों पर हुए हमलों एवं तोड़फोड़ की निंदा की। पार्टी ने इसके लिए अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। मार्च का नेतृत्व श्रीपुर उपजिला बीएनपी के पूर्व महासचिव और उपजिला परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अख्तरुल आलम मास्टर ने किया। यह मार्च सुबह करीब 11 बजे श्रीपुर-माओना हाइवे पर तेंगरा रोड जंक्शन से प्रारंभ हुआ।यह नगरपालिका की मुख्य सड़क से होते हुए और मुक्तिजोद्धा कार्यालय के पास से गुजरते हुए रेलवे गेट के पास स्थित बीएनपी कार्यालय के सामने एक रैली के साथ समाप्त हुआ। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बुधवार सुबह जारी बयान के अनुसार गृह मंत्रालय के आदेश पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढाका सहित आठ जिलों में बीजीबी की कुल 108 प्लाटून तैनात की गई हैं। इनमें से 56 प्लाटून अकेले गोपालगंज में तैनात हैं। ढाका के सावर और आशुलिया में 18 प्लाटून, नारायणगंज में छह, गाजीपुर में 18, भालुका में दो, गोपालगंज में 56, चट्टोग्राम में तीन और कॉक्स बाजार में एक प्लाटून तैनात की गई है। इसके अलावा चार प्लाटून को जरूरत पड़ने पर तैनात करने के लिए स्टैंडबाय पर रखा गया है।

एक नजर

गुजरात के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात

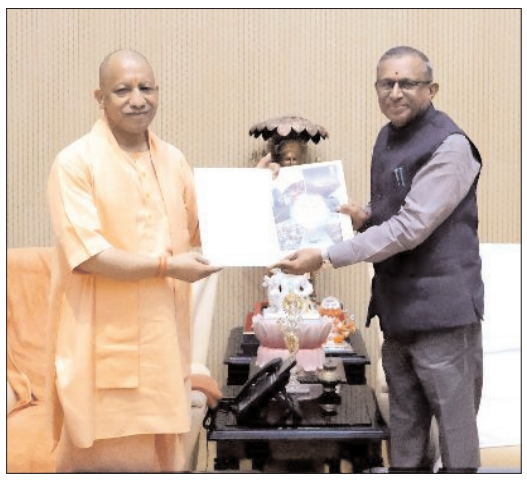

लखनऊ,एजेंसी। गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में गुजरात सरकार के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से उन्हें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में भाग लेने का आमंत्रण सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुजरात के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रमणभाई सोलंकी ने किया। इसमें सचिव आलोक कुमार पांडेय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग आयुक्त क्षिप्रा आग्रे तथा गुजरात सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी के साथ हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के आपसी संबंध मजबूत करने, सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझा विकास प्राथमिकताओं पर विचार साझा किया गया।। समिट से पहले चल रहे संपर्क अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से भी मुलाकात की। उन्हें समिट में भाग लेने और ऊर्जा एवं नगर विकास पर होने वाले ज्ञान सत्रों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की। उन्हें भी स्वास्थ्य क्षेत्र तथा फार्मा निर्यात पर केंद्रित प्रमुख सेमिनारों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बातचीत में नवीकरणीय ऊर्जा, भूमि सुधार और शासन से जुड़ी अन्य प्रमुख पहलों पर भी चर्चा हुई।

कम वेतन और नौकरी की अनिश्चितता के खिलाफ बिजली संविदाकर्मियों का सत्याग्रह

मीरजापुर। बिजली विभाग में वर्षों से काम करने के बावजूद नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज संविदाकर्मियों ने बुधवार को फतहां स्थित विद्युत वितरण मंडल कार्यालय पर सत्याग्रह किया। विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले कर्मचारियों ने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई और अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष श्यामनरायन यादव ने कहा कि संविदाकर्मी बिजली व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें कम वेतन और नौकरी की अनिश्चितता के बीच काम करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और सीधे विभाग से भुगतान जैसी घोषणाओं के बावजूद ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदाकर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा है। ठेकेदारी व्यवस्था के कारण कर्मचारियों का शोषण जारी है। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो 10 दिसंबर को लखनऊ में विशाल रैली निकालकर आवाज बुलंद की जाएगी। कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन 22 हजार रुपये और एसएसओ व लाइनमैन का वेतन 25 हजार रुपये करने की मांग की। साथ ही 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तय करने, 55 वर्ष की उम्र में हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने और टीजी-02 व श्रमिकों के रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर संविदाकर्मियों का समायोजन करने की मांग उठाई। ज्ञापन में दुर्घटना होने पर कर्मचारी का इलाज विभागीय खर्च पर कराने तथा मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 20 लाख रुपये का बीमा देने की मांग की गई। इसके अलावा मार्च 2023 की तीन दिवसीय हड़ताल के दौरान हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, पिछले पांच वर्षों में छंटनी किए गए कर्मियों को दोबारा काम देने और ड्यूटी के बाद आकस्मिक काम के लिए बुलाए जाने पर फेस अटेंडेंस से छूट देने की मांग भी शामिल रही।

व्यापार मेले में छाया रेलवे का पवेलियन, बुलेट ट्रेन से हाइड्रोजन ट्रेन तक दिखी भविष्य की झलक

नई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में भारतीय रेलवे का पवेलियन दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। 'भारतीय रेल : देश के विकास का पहिया' और 'विकास भी, विरासत भी' की थीम पर तैयार इस पवेलियन में रेलवे के गौरवशाली अतीत, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को एकसाथ प्रदर्शित किया गया है। यहां देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर, नमो भारत रैपिड रेल और चिनाब रेल पुल के मॉडल दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं, वर्चुअल रियलिटी (वीआर) तकनीक के जरिए कालका-शिमला रेल मार्ग की पहाड़ी वादियों में सफर का अनुभव भी लिया जा सकता है।

दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक चल रहे मेले के समापन में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में भारत मंडपम के हॉल नंबर-5 की पहली मंजिल पर बने रेलवे पवेलियन में सुबह से ही दर्शकों की आवाजाही बनी हुई है। पवेलियन का प्रवेश द्वार राजस्थान के जैसलमेर अमृत भारत स्टेशन की स्थापत्य शैली से प्रेरित है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक रेलवे सुविधाओं का मेल दिखाई दे। प्रवेश करते ही दर्शकों का होलोग्राम के माध्यम से स्वागत किया जाता है। इसके ऊपर लगी विशाल एनामॉर्फिक स्क्रीन पर थ्री-डी प्रभाव के साथ वंदे भारत और आधुनिक ट्रेनों की तस्वीरें



प्रदर्शित होती हैं। पवेलियन में आम लोगों के साथ छात्र और शोधकर्ता भी रेलवे की तकनीकी प्रगति तथा भविष्य की योजनाओं को करीब से देख और समझ सकते हैं। पवेलियन के 'इंजीनियरिंग के चमत्कार' खंड में देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का मॉडल विशेष आकर्षण है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे 508 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई शामिल हैं। पवेलियन में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार 10 नवंबर 2026 तक परियोजना में 459 किलोमीटर पायर वर्क, 375 किलोमीटर वायाडक्ट और 107 किलोमीटर ट्रैक लिंकिंग का काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना को देश में हाई-स्पीड रेल परिवहन की दिशा में बड़ी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पवेलियन में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में रेलवे की पहल को दर्शाने के लिए देश में निर्मित पहली हाइड्रोजन ट्रेन का मॉडल भी रखा गया है। 17 जुलाई 2026 को जींद-सोनीपत मार्ग पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया था। 10 कोच वाली इस ट्रेन की क्षमता 2,600 यात्रियों की और पावर 2,400 किलोवाट है। इसे दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बताया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली पैदा करती है। इसके संचालन में धुएं के बजाय पानी की भाप निकलती है।

तमिलनाडु सरकार ने न्यायपालिका और हिंदू आस्था का अपमान किया : विहिप

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने तमिलनाडु की टीवीके सरकार पर हिंदू आस्था और न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तिरुपरंकुंद्रम में भगवान मुरुगन की पवित्र पहाड़ी पर 'कार्तिगई महादीपम' महोत्सव के अवसर पर महादीप प्रज्ज्वलित नहीं होने देना सरकार की हठधर्मिता और न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। आलोक कुमार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा को रोकना भारतीय संविधान और न्यायपालिका का अपमान है। इससे भगवान मुरुगन के करोड़ों भक्तों की आस्था और विश्वास को भी ठेस पहुंची है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय अपने आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए कठोर दंड सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भगवान मुरुगन की पुण्यभूमि है। उन्हें तमिल भाषा और संस्कृति का शिल्पी भी माना जाता है। ऐसे आराध्य देव की पवित्र पहाड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महादीप प्रज्ज्वलित करने से रोकने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। विहिप अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तिरुपरंकुंद्रम की पहाड़ी को हिंदुओं के हत्यारों और जिहादी तत्वों से जोड़कर उसकी धार्मिक पहचान बदलने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान मुरुगन की पवित्र भूमि पर महादीप नहीं जलने देने के लिए सरकार जिस तरह का अड़ियल रवैया अपना रही है, उससे उसने भगवान मुरुगन के भक्तों से भी दुश्मनी मोल ले ली है। आलोक कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संविधान को चुनौती देने जैसा है। किसी भी निर्वाचित सरकार को राजनीतिक हठधर्मिता के चलते न्यायालय के आदेशों को ठुकराने का अधिकार नहीं है। हिंदूद्रोही राजनीति और ऐसी मानसिकता देश की राजनीति से समाप्त होगी तथा तमिलनाडु से भी ऐसी राजनीति की जल्द विदाई होगी। उल्लेखनीय है कि मदुरै के तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। पहाड़ी पर स्थित भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पास एक दरगाह भी है। विवाद पहाड़ी पर स्थित दीपथून (पत्थर के दीप स्तंभ) पर दीप जलाने को लेकर है। मद्रास उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2025 में दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद छह जनवरी 2026 को उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। 20 नवंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी थी।

नोएडा-गाजियाबाद में जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 248.50 एमबीपीएस

नई दिल्ली,। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से सितंबर 2026 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कराए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट में रिलायंस जियो की औसत डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक 248.50 एमबीपीएस दर्ज की गई। वहीं, एयरटेल की औसत डाउनलोड स्पीड 114.38 एमबीपीएस और वोडाफोन आइडिया (वीआई) की 94.30 एमबीपीएस रही। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)-महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की 4जी सेवा की औसत डाउनलोड स्पीड 5.49 एमबीपीएस दर्ज की गई। ट्राई ने बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया कि ये परीक्षण दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत एक से पांच सितंबर 2026 के बीच किए गए। इनका उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की मोबाइल नेटवर्क सेवाओं की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन करना था। परीक्षण में वॉयस और डेटा सेवाओं के साथ नेटवर्क कवरेज, कॉल ड्रॉप, कॉल स्थापित होने की दर, डाउनलोड और अपलोड स्पीड जैसे मानकों की जांच की गई। रिपोर्ट के अनुसार चारों दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में एयरटेल की औसत अपलोड स्पीड 25.11 एमबीपीएस, बीएसएनएल-एमटीएनएल की 1.72 एमबीपीएस, जियो की 18.71 एमबीपीएस और वीआई की 18.92 एमबीपीएस रही। कॉल ड्रॉप के मामले में एयरटेल के 1,139 सफलतापूर्वक स्थापित कॉल में से नौ, बीएसएनएल-एमटीएनएल के 1,071 में से 173, जियो के 1,146 में से 14 और वीआई के 1,158 में से दो कॉल ड्रॉप हुए।

कवरेज गैप के मामले में एयरटेल के कुल 1,27,346 नमूनों में से 1,053, बीएसएनएल-एमटीएनएल के 1,21,733 में से 79,985, जियो के 1,27,212 में से 2,146 और वीआई के 1,32,094 नमूनों में से 1,246 में कमजोर सिग्नल दर्ज किया गया। कॉल के दौरान तीन सेकंड से अधिक समय तक आवाज बंद रहने की घटनाएं एयरटेल में आठ, बीएसएनएल-एमटीएनएल में 10, जियो में 54 और वीआई में चार दर्ज की गईं। ट्राई ने नोएडा सेक्टर-121 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक के मार्ग के लिए भी अलग से आंकड़े जारी किए हैं। इस मार्ग पर जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 346.84 एमबीपीएस दर्ज की गई, जबकि एयरटेल की 175.41 एमबीपीएस, वीआई की 129.86 एमबीपीएस और बीएसएनएल-एमटीएनएल की 3.39 एमबीपीएस रही। इस मार्ग पर औसत अपलोड स्पीड एयरटेल की 19.29 एमबीपीएस, बीएसएनएल-एमटीएनएल की 1.02 एमबीपीएस, जियो की 27.94 एमबीपीएस और वीआई की 29.08 एमबीपीएस दर्ज की गई। इस विशेष मार्ग पर कवरेज गैप के नमूने एयरटेल के 2,793 में से एक, बीएसएनएल-एमटीएनएल के 2,743 में से 1,646, जियो के 2,849 में से 12 और वीआई के 2,973 में से चार रहे।

भाजपा का 'प्लान 55', यूपी में जिन सीटों पर अब तक नहीं मिली जीत, वहां संगठन को मजबूत करने की तैयारी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी की चुनावी रणनीति में अब उन विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान देने की तैयारी है, जहां भाजपा को अब तक जीत हासिल नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक इसी कड़ी में पार्टी का 'प्लान 55' चर्चा में है। इसके तहत प्रदेश की 55 ऐसी विधानसभा सीटों को अलग श्रेणी में रखकर उनके लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इस कवायद का मकसद इन सीटों पर संगठन की कमजोरियों को समझना और जमीनी स्तर पर पार्टी की मौजूदगी बढ़ाना है। पार्टी के लिए ये सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने की व्यापक तैयारी के बीच इन 55 सीटों के लिए अलग से काम करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार इन सीटों पर पार्टी का फोकस केवल चुनाव के समय प्रचार करने तक सीमित नहीं रहेगा। संगठनात्मक स्तर पर यह समझने की कोशिश होगी कि किन कारणों से पार्टी को इन क्षेत्रों में सफलता नहीं मिल पाई। स्थानीय राजनीतिक समीकरण, सामाजिक प्रतिनिधित्व, प्रत्याशियों की स्थिति और बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता जैसे पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। हाल ही में लखनऊ और मथुरा में हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर विशेष ध्यान देने और नेताओं की जिम्मेदारियां तय करने पर चर्चा हुई । इन क्षेत्रों में बूथ समितियों को फिर से सक्रिय करने और केंद्रीय नेताओं के दौरे कराने की रणनीति भी बनाई गई है। भाजपा की रणनीति में स्थानीय संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। पार्टी



इन क्षेत्रों में स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर सकती है। इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी समय रहते फीडबैक जुटाने की रणनीति पर काम हो सकता है। पार्टी का जोर चुनाव से कुछ महीने पहले नहीं, बल्कि अभी से इन क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहने पर है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक तैयारी का लक्ष्य रखा है। इस तरह 'मिशन 403' के बीच 'प्लान 55' को उन विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित विशेष रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। कुल मिलाकर, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति में उन क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जहां पार्टी को पिछले चुनाव में सफलता नहीं मिली। अब देखना होगा कि इस विशेष योजना के तहत संगठनात्मक स्तर पर क्या बदलाव किए जाते हैं और इन सीटों के लिए जिम्मेदारियां किस तरह तय होती हैं।

भारत गौरव उत्सव में संघ पर चार पुस्तकों का विमोचन

नई दिल्ली। चाणक्य वार्ता प्रकाशन समूह की दिल्ली इकाई की ओर से आयोजित 'भारत गौरव उत्सव-2026' के अंतर्गत संघ शताब्दी पुस्तक शृंखला के कार्यक्रम में तीन सत्रों में अलग-अलग पुस्तकों का विमोचन किया गया। तीन सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम में चार पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों ने परिचर्चा की। कार्यक्रम में प्रसिद्ध नृत्यांगना शुभदा वराडकर एवं उनके सहयोगियों ने 'केशव कल्प' की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का शुभारंभ राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वी. शांता कुमारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ हुआ। इसके बाद चाणक्य वार्ता के संपादक डॉ. अमित जैन ने स्वागत भाषण दिया और मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर मृत्युंजय कुमार झा की पुस्तक 'स्वतंत्रता संग्राम और डॉ. हेडगेवार' तथा डॉ. अमित जैन की पुस्तक 'बहुआयामी संघ' का विमोचन किया गया। विभिन्न समुदायों से आए लोगों ने शांता कुमारी का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

कार्यक्रम के विशेष अतिथि संत ईश्वर फाउंडेशन के अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा कि संघ के सौ वर्षों का इतिहास केवल समय की यात्रा नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और बलिदान की गौरवगाथा है। आज आवश्यकता है कि व्यक्ति और समाज अपने अस्तित्व से आगे बढ़कर राष्ट्र के अस्तित्व के लिए कार्य करें। भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति



है। उन्होंने नारी को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एसके आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आर्य समाज की विचारधारा में समानता है। दोनों ही संगठन राष्ट्र एवं समाज निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित पीढ़ी तैयार की है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोशियारी ने राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता कुमारी को त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि संघ व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसी भावना को आत्मसात कर ले तो समाज का निर्माण स्वत: हो जाएगा। उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में परिवार और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि किसी प्रकाशन संस्थान का दस वर्षों तक निरंतर सक्रिय रहना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना समाज को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण की भावना से हुई थी। सौ वर्षों की यात्रा में संघ ने राष्ट्र सेवा के साथ समाज को संस्कार और संस्कृति देने का कार्य किया है। आज बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक है। महिलाओं को घर की चारदीवारी से आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए तथा संघ के पंच परिवर्तन को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वी. शांता कुमारी ने कहा कि डॉ. हेडगेवार ने चाणक्य नीति से प्रेरणा लेते हुए स्वयंसेवकों को कठिन परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य से विचलित न होने का संदेश दिया था। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानें तथा परिवार एवं समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में डॉ. अमित जैन द्वारा लिखित पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : शताब्दी यात्रा' (कॉफी टेबल बुक) का विमोचन किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्य सचिव एवं मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. टीवीएसएन प्रसाद तथा पंजाब सरकार के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव के. शिवा प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त किए। तीसरे सत्र का शुभारंभ प्रसिद्ध नृत्यांगना शुभदा वराडकर एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम 'केशव कल्प' से हुआ। इसके बाद महेंद्र विक्रम सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'शुभांक संघ काव्यांजलि' का विमोचन किया गया।

हाथरस: दो बार विधायक रहे नवाब छाबी मियां राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक



हाथरस,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे नवाब मुस्तमंद अली खां उर्फ छाबी मियां को बुधवार दोपहर बाग वाली मस्जिद स्थित कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मंगलवार को आगरा के बालूगंज स्थित आवास पर उनका निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र की कई हस्तियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बुधवार दोपहर करीब दो बजे उनका पार्थिव शरीर कब्रिस्तान पहुंचा।

इस दौरान पुलिस की सलामी टुकड़ी ने राइफलें झुकाकर उन्हें अंतिम सलामी दी। विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व विधायक प्रताप चौधरी और पूर्व विधायक डॉ. अनिल चौधरी ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के नेता गिरेंद्र चौधरी, जिला पंचायत सदस्य ईशान चौधरी और केशव देव चौधरी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सादाबाद इंटर कॉलेज के प्रबंधक कुंवर महमूद अली खां ने अंतिम विदाई दी। इस मौके पर एसडीएम रितु सिरोही, पुलिस उपाधीक्षक योगेंद्र कृष्ण नारायण सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। छाबी मियां की सादाबाद क्षेत्र में अलग पहचान थी। वह वर्ष 1985 में लोकदल के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वर्ष 1989 में लोकदल का जनता दल में विलय होने के बाद चुनाव चिह्न बदलकर चक्र हो गया। इसके बावजूद उन्होंने दूसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन पर क्षेत्र के लोगों और समर्थकों ने शोक जताया।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)